

## एक नजर

यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त,  
दो गंभीर घायल

विकासनगर। कालसी तहसील क्षेत्र के साहिवा-नरगा मोटर मार्ग पर बुधवार देर रात एक यूटिलिटी वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। वाहन में सवार दो लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। प्राथमिक उपचार के बाद दोनों घायलों को हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है। गुरुवार देर रात शादी समारोह से लौटते वक्त यूटिलिटी वाहन नरगा गांव के पास अनियंत्रित होकर गहरी खाई में जा गया। स्थानीय ग्रामीणों को दुर्घटना की सूचना मिलने पर ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंचे। खाई से दो घायल लोगों को निकालकर उपचार के लिए सीएचसी साहिवा में भर्ती कराया। अस्पताल के प्रभारी चिकित्साधिकारी डॉ. अश्वय आनंद ने बताया कि बुधवार देर रात वाहन दुर्घटना में घायल हुए टीकम सिंह, गोपाल सिंह निवासी सैंज गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को प्राथमिक उपचार के बाद हायर सेंटर रेफर कर दिया गया है।

दस साल में नियमित करने के  
हाईकोर्ट के आदेश का हो पालन

देहरादून। उत्तराखंड विद्युत संचिका कर्मचारी संगठन ने संचिका कर्मचारियों को दस साल में नियमित करने के हाईकोर्ट के आदेश का तत्काल लागू करने की मांग की। सचिव उज्ज्वला को भेजे पत्र में संगठन अध्यक्ष विनोद कवि ने कहा कि उज्ज्वला को तीनों निर्णयों में तैनात उपनल कर्मचारियों को नियमितकरण का लाभ दिया जाए। कवि ने कहा कि हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि ऐसे संचिका, दैनिक भोगी कर्मचारी, जिनकी सेवाओं को दस साल हो गए हैं, उन्हें नियमितकरण का लाभ दिया जाए। इस दायरे में उज्ज्वला को तीनों निर्णयों के कर्मचारी आ रहे हैं। उज्ज्वला निर्णयों के उपनल कर्मचारियों को नियमित किए जाने को लेकर पहले भी श्रम न्यायालय और फिर हाईकोर्ट फैसला दे चुके हैं। इसके तहत दायरे में आने वाले उपनल कर्मचारियों को नियमित किया जाना था। जो कर्मचारी नियमितकरण के दायरे में नहीं आ रहे हैं, उन्हें समान काम का समान वेतन दिया जाना था। इन आदेशों को मानने की बजाय सरकार हाईकोर्ट के आदेश को खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई। कहा कि अब जब हाईकोर्ट साफ कर चुका है कि दस साल की सेवा वाले कर्मचारियों को नियमित किया जाए। तो उत्तराखंड में जल्द इस आदेश को सख्ती से लागू किया जाए। क्योंकि उपनल कर्मचारी भी विभागों में फोर्ड से लेकर ऑफिसों का काम संभाले हुए हैं।

सीरियल बम ब्लास्ट केस में 30  
साल बाद आया फैसला, अब्दुल  
करिम टुंडा बरी- दो दोषी करार

अजमेर, सीरियल बम ब्लास्ट केस में अजमेर की टाडा कोर्ट ने आतंकी अब्दुल करिम टुंडा को वीरवार को बरी कर दिया जबकि, इरफान और हमीदुद्दीन को दोषी माना गया है। सीरियल बम ब्लास्ट केस में करीब 30 साल बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया है। टुंडा, इरफान और हमीदुद्दीन को लेकर पुलिस गुरुवार सुबह करीब सवा 11 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच टाडा कोर्ट पहुंचे। कोर्ट ने 6 दिसंबर 1993 को लखनऊ काफ़ूर, हैदराबाद, सूत और मुंबई की ट्रेनों में हुए सिलसिलेवार बम धमाके के मामले में आरोपी थे। 20 साल पहले 28 फरवरी 2004 को टाडा कोर्ट ने ही मामले में 16 अभियुक्तों को उभरके की सजा सुनाई थी। मामले को लेकर अजमेर टाडा कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि टुंडा के खिलाफ कोई डायरेक्ट एवीडेंस नहीं मिला है। इसलिए उन्हें बरी कर दिया।

लॉरेन्स स्कूल शिक्षकों को कोरोना  
काल का पूरा वेतन दे - हाई कोर्ट

इंदौर, हाई कोर्ट इंदौर ने लॉरेन्स स्कूल के शिक्षकों और कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के आदेश दिए हैं। कोर्ट निर्देश में यह भी कहा कि जिन शिक्षकों व कर्मचारियों की सेवा समाप्त हो गई है, उनमें जो नौकरी जारी रखना चाहते हैं वे पुनः ज्वाइनिंग दे सकते हैं। कोर्ट इंदौर ने यह आदेश शिक्षकों और कर्मचारियों की याचिकाओं का निराकरण करते हुए उक्त आदेश दिया। शिक्षकों और कर्मचारियों द्वारा कोरोना काल का वेतन मांगने पर स्कूल प्रबंधन ने 12 जून 2021 को पत्र जारी कर उनकी सेवाएं अप्रैल 2020 से ही समाप्त मान ली थी। शिक्षकों और अन्य ने इस आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की थीं।

याचिकाओं में कहा गया था कि प्रमुख सचिव शिक्षा विभाग ने 24 अप्रैल 2020 को एक आदेश जारी कर सभी निजी स्कूलों से शिक्षकों और अन्य कर्मचारियों को कोरोना काल का पूरा वेतन देने के लिए कहा था। विशेषी वकील को कहा कि नौ बजे तक सुनवाई चल सकती थी।

## 17 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान

# मोदी कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर

नई दिल्ली, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को बैठक हुई जिसमें कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बताया कि मोदी कैबिनेट ने आगामी खरीफ सत्र 2024 के लिए फॉस्फोरस और पोटाश (पीएनडके) उर्वरकों के लिए पोषण तत्व आधारित सिल्विडी (एनबीएस) की दरें गुरुवार को तय कीं। खरीफ सत्र में सरकार द्वारा इसके लिए बजट से 24,400 करोड़ रुपये से अधिक की सहायता दिए जाने का अनुमान है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल की गुरुवार को यहां हुई बैठक में पीएनडके उर्वरकों पर एनबीएस की दरें निर्धारित करने के साथ-साथ उर्वरकों की तीन नई श्रेणियों को भी पोषण आधारित सिल्विडी योजना के अन्तर्गत लाने का फैसला किया गया है। बैठक के बाद जारी विज्ञापित के अनुसार, खरीफ सत्र 2024 के लिये इस योजना के तहत बजट से करीब 24,420 करोड़ रुपये की सहायता की जरूरत



पड़ेगी। खरीफ फसल सत्र हर वर्ष पहली अप्रैल से 30 सितंबर तक चलता है। विज्ञापित में कहा गया कि इस निर्णय से किसानों को आगामी खरीफ सत्र में फसलों के लिये उचित दर पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित की

होगी। सरकार का कहना है कि एनबीएस योजना में उर्वरकों की तीन नयी श्रेणियों को शामिल किये जाने से किसानों को उर्वरकों के चयन के और विकल्प उपलब्ध होंगे तथा खेतों की ओर उर्वरता बनाये रखने में मदद मिलेगी। सरकार का कहना है कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में उर्वरकों और उर्वरकों के उत्पादन में लगने वाली सामग्री की कीमतों में हाल के परिवर्तन को देखते हुये, एनबीएस की दरों की समीक्षा की गयी है। केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने योग नियंत्रण और महामारी निपटने की तैयारी के लिये राष्ट्रीय एक स्वास्थ्य मिशन का नेतृत्व करने के वास्ते नागपुर के ह्यराष्ट्रीय एक स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के पद के सृजन को स्वीकृति प्रदान की है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले केंद्र सरकार ने बड़ा ऐलान किया है। मोदी सरकार ने 17 लाख लोगों को रोजगार देने की घोषणा की। साथ ही कैबिनेट की बैठक में पीएम सूर्य वर मुण्ट बिजली योजना को मंजूरी मिल गई है।

पांच मुद्दों पर बात के साथ  
कर सकते हैं सिंधिया पर  
कटाक्ष : राहुल गांधी

भोपाल, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की भात जोड़ो न्याय यात्रा दो मार्च तक मद्र में रहेगी। यात्रा ग्वालियर चंबल संभाग में ज्यादा रहेगी। यह वही इलाका है जहां 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को सबसे ज्यादा फायदा हुआ था। वर्ष 2023 के विधानसभा चुनाव में भी ग्वालियर चंबल में मद्र के किसी अन्य हिस्से की तुलना में कांग्रेस को सबसे ज्यादा सीटें मिलीं, हालांकि पांच साल पहले हुए चुनाव में हुए सीटों के मुनाफे से कुछ कम है। न्याय यात्रा के जरिए इस इलाके में कांग्रेस अपना जनाधार वापस लेने की कोशिश करेगी। वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस अंचल में कांग्रेस के लिए अभी भी बहुत पोटेंशियल है। वहीं इस क्षेत्र में ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती बने हुए हैं। कांग्रेस नेताओं का मानना है कि पांच न्याय की बातों के अलावा राहुल गांधी अपने संबोधनों के दौरान सिंधिया पर भी प्रहार कर सकते हैं। उनका मानना है कि महल के खिलाफ राहुल गांधी कुछ बोलेंगे तो कांग्रेस को लाभ होगा।

## हाई कोर्ट ने प्रमुख सचिव का आदेश किया निरस्त

• नदीम जैदी को अवसर दिए जाने का दिया निर्देश

नैनीताल। हाई कोर्ट ने उत्तराखंड वक्फ बोर्ड के गढ़वाल क्षेत्र के न्यायिक सदस्य के पद पर के लिए जारी प्रमुख सचिव अल्पसंख्यक विभाग, एल फनई के 22 दिसंबर 2023 के आदेश को निरस्त कर दिया है।

मुख्य न्यायोधीश न्यायमूर्ति ऋतु बाहरी और न्यायमूर्ति राकेश थपलियाल की खंडपीठ में वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर पूर्व सदस्य नदीम जैदी की याचिका पर सुनवाई हुई, जिसमें कहा गया था कि प्रमुख सचिव की ओर से याचिकाकर्ता को इस वजह से दो वर्ष का सेवा विस्तार नहीं दिया था, की उनकी 2020 में तीन वर्ष की नियुक्ति के विरुद्ध कुछ शिकायतें प्राप्त थीं।

नदीम जैदी को जून 2020 में नियुक्ति भी प्रमुख सचिव एल फनई की ओर से की गई थी, फिर नियुक्ति के संदर्भ में प्राप्त शिकायतों के आधार पर



उन्हें सेवा विस्तार देने से मना कर दिया था।

खंडपीठ ने प्रमुख सचिव का आदेश निरस्त करते हुए स्पष्ट किया कि शासन को नदीम जैदी को व्यक्तिगत सुनवाई

का अवसर देते हुए शिकायत पत्र सौंपने होंगे, उसके बाद ही वह वक्फ बोर्ड में न्यायिक सदस्य के रिक्त चल रहे पद पर नियुक्ति संबंधी कोई आदेश पारित कर सकते हैं।

## मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खेल विभाग की समीक्षा की

देहरादून। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विधानसभा भवन में खेल विभाग के साथ पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुनि की रती टिहरी तथा इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में लाइफिंग के कार्यों की समीक्षा की। सीएस राधा रतूड़ी ने पूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, मुनि की रती में बहुउद्देशीय भवन को पहाड़ी वास्तुकला से निर्मित एवं सुसज्जित करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही उन्होंने इन्दिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, हल्द्वानी में कार्यों की भी समीक्षा की। मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने खेल विभाग को राज्य में खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर के कार्यों को मिशन मोड पर जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए।

सीएस ने कहा कि राज्य में विकसित खेल इन्फ्रास्ट्रक्चर उत्तराखण्ड में प्रस्तावित राष्ट्रीय खेलों के आयोजन के साथ ही भविष्य में दीर्घ अवधि तक राज्य के खिलाड़ियों तथा युवाओं को लाभांनित करेगा। बैठक में विशेष



प्रमुख सचिव अमित सिन्हा, सचिव विजय कुमार जोगदण्डे तथा जितेन्द्र सम्बन्धित विभागों के अधिकारी अरविंद सिंह ह्यांकी, अपर सचिव कुमार सोनकर सहित खेल एवं उपस्थित थे।

## देश के प्रभावशाली लोगों में शामिल हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर धामी देश के 100 ताकतवर व प्रभावशाली भारतीयों की सूची में 61वें स्थान पर हैं। अपने सख्त फैसलों को लेकर उनकी रैंक में बड़ा सुधार हुआ है एक राष्ट्रीय मीडिया हाउस ने देश के 100 ताकतवर भारतीयों की सूची आईई-2024 जारी की है।

इसमें प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी पहले जबकि दूसरे स्थान पर गृह मंत्री अमित शाह हैं। इसके अलावा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, विदेश मंत्री एस जयशंकर, सूची के सीएम योगी आदित्यनाथ क्रमशः तीसरे, चौथे, पांचवें व छठे स्थान पर हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, निर्मला सीतामन, भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और प्रमुख उद्योगपति गौतम अडानी टॉप-10 की सूची में हैं। इस सूची में देश के प्रमुख राजनीतिज्ञों के अलावा उद्योगपतियों, अभिनेताओं और खिलाड़ियों को स्थान दिया गया है। सूची में मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने भी बड़े फैसलों से मजबूत स्थान बनाया है। वे इस सूची में 61 वें स्थान पर हैं, जबकि पिछले वर्ष उनकी रैंकिंग 93 वें स्थान पर थी।



पिछले साल नवंबर माह में उत्तराखण्ड के सिलवारा सुरंग हदसे के बाद सीएम धामी का रेक्व्यू अभिधान देश-दुनिया के सामने नज़ीर बना। इसके अलावा देश में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) विधेयक का मॉडल पेश किया और हल्द्वानी में भड़के दंगों पर 24 घंटे के

न चलेगी ट्रेनें, न होगा किसी सरकारी दफ्तर में काम, हड़ताल का हो गया ऐलान

नई दिल्ली, किसान आंदोलन के दूसरे चरण के बीच कर्मचारी संगठनों ने देशभर में अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान कर दिया है। यह हड़ताल 1 मई को होगी और केंद्र सरकार को 19 मार्च को नोटिस देते हुए ट्रेन और डिफेंस इंडस्ट्री को बंद करते हुए केंद्र सरकार व राज्य सरकारों के दफ्तरों में कामकाज ठप रहेगा।

ज्वाइंट फोरम फॉर रिटोरेशन ऑफ ऑल्ड पेंशन स्कीम ने सर्वसम्मति से फैसला लिया है कि 19 मार्च को संबंधित प्रशासनों को हड़ताल को लेकर नोटिस दिया जाएगा। जेएफआरओपीएस के संयोजक और ऑल इंडिया रेलवेमेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) के महासचिव शिव गोपाल मिश्रा ने बताया कि इस मुद्दे पर केंद्र के साथ चर्चा विफल होने के बाद हड़ताल पर जाने का निर्णय लिया गया। महासचिव शिव गोपाल मिश्रा कैबिनेट सचिव की अध्यक्षता वाली संयुक्त सलाहकार मशीनरी (जेसीएम) के सचिव (कर्मचारी पक्ष) भी हैं।

## निचली अदालतों और हाई कोर्ट के स्टे ऑर्डर अपने आप रद्द नहीं होते, सुप्रीमकोर्ट का बड़ा फैसला



नई दिल्ली, स्टे ऑर्डर को लेकर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने अहम फैसला सुनाया है। शीर्ष कोर्ट ने कहा कि ट्रायल कोर्ट या हाई कोर्ट द्वारा दिया गया स्टे ऑर्डर छह महीने के बाद स्वतः खत्म नहीं हो सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संवैधानिक अदालतों को मामलों के निपटारे के लिए समयसीमा तय करने से बचना चाहिए। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि

असाधारण परिस्थितियों में ऐसा किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा कि ये नियम है कि दीवानी और आपराधिक मामलों में दिया गया स्थान आदेश 6 महीने के बाद स्वतः समाप्त नहीं होता है जब तक कि आदेशों को विशेष रूप से बढ़ाया न जाए। इसी के साथ सर्वोच्च न्यायालय ने 2018 के अपने ही उस आदेश को पलट दिया है, जिसके तहत पहले के अंतरिम आदेशों को, जब तक कि विशेष रूप से उन्हें बढ़ाने का आदेश न स्पष्ट हो, छह महीने बाद अपने आप रद्द मान लिया जाता था। तब सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि किसी अंतरिम स्टे ऑर्डर को बढ़ाने के लिए अदालतों (हाईकोर्ट या निचली अदालतों) को स्पष्ट आदेश जारी करने होंगे।

## ध्वनिमत से बजट पास, सत्र की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित



देहरादून। उत्तराखंड विधानसभा में सत्र के चौथे दिन वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए करीब 89 हजार करोड़ का बजट ध्वनिमत से पास हो गया। इसके साथ ही सत्र की कार्यवाही तय दिनों से एक दिन पहले गुरुवार को ही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। इस पर 26 फरवरी से 29 फरवरी तक सदन की कार्यवाही 28 घंटे 25

मिनट तक चली। बता दें कि धामी सरकार ने मंगलवार को विधानसभा में 89 हजार करोड़ से ज्यादा का बजट पेश किया था। जिसमें राजस्व के लिए लेखे का व्यय 55815.77 करोड़ और पूंजीगत लेखे का व्यय 33414.30 करोड़ रहा। इस बार बजट में 15 फीसदी बढ़ोतरी की गई। इसमें सरकार ने 14538 करोड़

पांच लाख के जेंडर बजट का भी प्रावधान किया है। बजट में गरीब, किसान, युवा, महिला वर्ग पर खास फोकस है। सूचना प्रौद्योगिकी और आधुनिक तकनीक के माध्यम से सरकारी तंत्र को सरल-सुगम बनाकर विकास की नई राहें तैयार करने के साथ हर पीढ़ी के सपनों को साकार करने का संकल्प लिया गया है।

## सभी तहसीलों में एक-एक फायर स्टेशन हो रहे स्थापित - योगी आदित्यनाथ

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज यहां अपने सरकारी आवास पर आयोजित एक कार्यक्रम में अग्नि सुरक्षा कवच के सुदृढीकरण हेतु 38 अग्निशमन केन्द्रों का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया। उन्होंने 35 अग्निशमन वाहनों का प्लेग ऑफ भी किया। उन्होंने अग्निशमन एवं जीवन रक्षा कार्य हेतु विशिष्ट उपकरणों का अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को सम्बोधित करते हुए कहा कि संकट के समय अग्निशमन सेवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होती है। प्रदेश सरकार ने अग्निशमन से जुड़े कानूनों के व्यापक रिकॉर्म तथा इन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए समयबद्ध तरीके से कार्य किया है। इसके परिणामस्वरूप अग्निशमन विभाग ने बेहतर इमरजेंसी सेवाएं प्रदान करने के लिए स्वयं को तैयार किया है। आज यहां 25 जनपदों के 34 अग्निशमन केन्द्रों का लोकार्पण, 04 नए अग्निशमन केन्द्रों का शिलान्यास तथा 35 फायर टेंडर का प्लेग ऑफ किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि प्रदेश में वर्ष 1944 में अग्निशमन विभाग का गठन किया गया था। वर्ष 1944 से 2017 तक राज्य में कुल 288 फायर स्टेशन स्थापित हुए। विगत 07 वर्षों में हमारी सरकार ने 71 नये फायर स्टेशन स्थापित किए हैं।

## जयन्त कोटद्वार नाम के समाचार पत्र से संबंधित ब्यौरा

### फार्म-4 (नियम 8)

क्र.सं.	प्रकाशन स्थान-	कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड
1.	प्रकाशन की अवधि	-दैनिक
2.	मुद्रक का नाम	-नागेन्द्र उनियाल
3.	व्या भारत का नागरिक है	-हां
4.	व्या भारत का नागरिक है	-हां
5.	पता	-बदरिनाथ मार्ग, कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड
6.	संपादक का नाम	-नागेन्द्र उनियाल
7.	व्या भारत का नागरिक है	-हां
8.	पता	-बदरिनाथ मार्ग, कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड
9.	उन व्यक्तियों के नाम व पते जो समाचार पत्र के स्वामी हैं तथा जो समस्त पूंजी के एक प्रतिशत से अधिक के साझेदार या हिस्सेदार हों।	-एकल स्वामित्व नागेन्द्र उनियाल
10.	में नागेन्द्र उनियाल एतद्वारा घोषित करता हूं कि मेरी अधिकतम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार उपरोक्त विवरण सत्य है।	-बदरिनाथ मार्ग, कोटद्वार (गढ़वाल) उत्तराखण्ड
11.	दिनांक 01 मार्च 2024	(हो) नागेन्द्र उनियाल (प्रकाशक)



## डेस्टिनेशन उत्तराखण्ड

राज्य में निवेशकों के लिए बेहतर  
आयाम तैयार कर रही प्रदेश सरकार



**पुष्कर सिंह धामी**  
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड



**नरेन्द्र मोदी**  
प्रधानमंत्री

पहाड़ी इलाकों में निजी औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के लिए विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति की घोषणा की गई। यह नीति औद्योगिक क्षेत्र की निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए प्रस्तावित की गई थी

## औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना पर है धामी सरकार का जोर

विशेष एकीकृत औद्योगिक प्रोत्साहन नीति राज्य में औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने से जुड़ी एक प्रमुख पहल है। इसके माध्यम से रोजगार के अवसर सृजित हुए हैं। राज्य के दूरस्थ इलाकों में औद्योगिक विकास के साथ-साथ सुविधाओं को विस्तार मिल सका है। यहां की सड़कों, नालियों, प्रकाश की व्यवस्था जैसी मूलभूत सुविधाओं के व्यय पर 50 प्रतिशत की सब्सिडी अधिकतम 50 लाख रुपये का प्रावधान किया गया। केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित विशेष औद्योगिक पैकेज के समाप्त होने और सिडकुल की ओर से विकसित एकीकृत उद्योगों के लिए भूमि की सीमित उपलब्धता को देखते हुए निजी भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए इस नीति को लागू किया गया। इसके प्रमुख बिंदु ये हैं:

- निजी औद्योगिक एस्टेट की स्थापना के लिए मैदानी भाग में कम से कम 30 एकड़ की जमीन और पहाड़ी इलाकों में कम से कम 02 एकड़ या इससे अधिक की भूमि का होना जरूरी है। यह भी कहा गया है कि एमएमएमई इकाइयों की स्थापना के लिए जमीन देना जरूरी होगा। बड़े औद्योगिक स्थानों के लिए न्यूनतम 10 स्वतंत्र एमएमएमई इकाइयां और पहाड़ी क्षेत्रों के

न्यूनतम 05 स्वतंत्र एमएमएमई इकाइयां निर्धारित की गई हैं।

- निजी क्षेत्र में आईटी पार्क/ बायो टेक्नोलॉजी पार्क के विकास के लिए सीडा के प्रचलित भवन उपनियमों के अनुसार न्यूनतम 18000 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्रफल होना जरूरी है।
- निजी औद्योगिक एस्टेट या क्षेत्र के लिए निवेशक या प्रमोटर अपने संसाधनों से भूमि की व्यवस्था करेंगे।
- औद्योगिक संपदाओं या इन क्षेत्रों के विकास के लिए सीडा/यूनीफाइड बिल्डिंग बाय लॉज का पालन करना होगा और सीडा नियामक प्राधिकरण के रूप में कार्य करेगा।
- ऐसे औद्योगिक क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के रूप में आन्तरिक सड़कों, नालियों, प्रकाश व्यवस्था व अन्य सामान्य सुविधा प्रदान करने की जिम्मेदारी आस्थान के प्रवर्तक की होगी।
- निजी औद्योगिक एस्टेट या क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक अनुमोदन/ विनियमन की प्रक्रिया दो चरणों की होगी। पहले चरण में औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना के लिए सैद्धान्तिक स्वीकृति दी जायेगी। जबकि दूसरे चरण में भूमि पर सीडा लेआउट पर अनुमोदन और प्रमाण पत्र दिखाने के बाद औपचारिक

अधिसूचना जारी की जाएगी।

- बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी औद्योगिक क्षेत्रों या इसके बाहर के क्षेत्रों के लिए 100 करोड़ रुपये की राशि का कोश बनाया जाएगा। सिडकुल इस फंड को संचालित करेगा। इस निधि से औद्योगिक क्षेत्र में किए गए कुल पूंजी निवेश की तुलना में 2 प्रतिशत की धनराशि खर्च की जाएगी।
- इस नीति के तहत क्षेत्र के भीतर बुनियादी सुविधाओं पर किए गए पूंजी निवेश के सापेक्ष चार चरणों में 10 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से पूंजीगत निवेश किया जाएगा। निजी औद्योगिक प्रतिष्ठानों में सीईटीपी की स्थापना के लिए अचल पूंजी निवेश का 40 प्रतिशत, अधिकतम 01 करोड़ रुपये तक अनुदान दिया जायेगा।
- यह नीति अधिसूचना जारी होने की तिथि से लागू होगी और आगामी 05 वर्ष तक प्रभावी रहेगी।



## उत्तराखण्ड की लॉजिस्टिक नीति-2023 के प्रमुख बिन्दु

### पात्र गतिविधियां

- लॉजिस्टिक पार्क, इनलैंड कन्टेनर डिपो, वेयरहाउस, ट्रक टर्मिनल, लॉजिस्टिक वाहन, कोल्ड स्टोरेज आदि।
- ईको लॉजिस्टिक या ग्रीन लॉजिस्टिक/ टेक्नोलॉजी लॉजिस्टिक सुविधाओं का विकास।

### वित्तीय प्रोत्साहन

- परियोजना लागत पर 10 से 25 प्रतिशत तक वित्तीय प्रोत्साहन।
- 50 करोड़ रुपये तक की परियोजना लागत पर अधिकतम 08 करोड़ रुपये, 50 करोड़ रुपये से 150 करोड़ रुपये तक के परियोजना लागत पर अधिकतम 24 करोड़ रुपये व 150 करोड़ रुपये से अधिक परियोजना लागत पर अधिकतम 32 करोड़ रुपये तक का अनुदान।
- वेयरहाउसिंग सुविधा के लिए पर्वतीय क्षेत्र में न्यूनतम 2.50 करोड़ रुपये निवेश के साथ 5000 वर्गफुट क्षेत्रफल और मैदानी क्षेत्र में न्यूनतम 05 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 10000 वर्गफुट क्षेत्रफल की आवश्यकता।
- ट्रक टर्मिनल के लिए न्यूनतम 5 करोड़ रुपये निवेश के साथ 45,000 वर्गफुट भूमि की आवश्यकता।
- कोल्ड स्टोरेज के लिए न्यूनतम क्षेत्रफल 5000 वर्गफुट।

## फैक्ट्री से बरामद हुआ नकदी दवाओं का जखीरा, दो गिरफ्तार



फैक्ट्री में नकली दवा बनाने के आरोपी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : भाबर क्षेत्र के अंतर्गत सिगडू सिडकुल इंडस्ट्रियल एरिया में स्थित एक फैक्ट्री से नकदी दवाओं का जखीरा बरामद हुआ है। मामले में पुलिस ने फैक्ट्री स्वामी सहित एक अन्य को गिरफ्तार किया है।

वर्ष 2021 में कोरोना काल के दौरान उक्त फैक्ट्री का नाम रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने व बेचने में भी सामने आया था। तब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने फैक्ट्री में छापारा था। स्टेट विजिलेंस ऑफिसर तेलंगाना

### कोरोना काल में रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने व बेचने में भी सामने आया था नाम हैदराबाद पुलिस व कोटद्वार पुलिस ने फैक्ट्री में संयुक्त रूप से मारा छापारा

किरण कुमार जानू बताया कुछ दिन पूर्व टीम ने तेलंगाना में नकली दवाओं की खेप पकड़ी थी।

जिसके तार कोटद्वार स्थित सिगडू सिडकुल की एक फैक्ट्री से जुड़ रहे थे। जिसके तार कोटद्वार स्थित सिगडू सिडकुल की एक फैक्ट्री से जुड़ रहे थे। जिसके तार कोटद्वार स्थित सिगडू सिडकुल की एक फैक्ट्री से जुड़ रहे थे।

लिए जिले के उच्चाधिकारियों से संपर्क किया गया। जिसके बाद कोटद्वार पुलिस व तेलंगाना की टीम ने फैक्ट्री में छापेमारी की। टीम ने बुधवार से छापेमारी शुरू कर दी थी। तेलंगाना की टीम ने बताया कि मामले में हैदराबाद के एक थाने में

### कोरोना काल में भी आई थी चर्चाओं में

यह वही फैक्ट्री वही है, जिसमें कोरोनाकाल के दौरान अप्रैल 2021 में दिल्ली में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन बनाने व बेचने का नाम सामने आया था। तब दिल्ली की क्राइम ब्रांच ने यहां छापारा था, हालांकि तब यहां कुछ भी बरामद नहीं हुआ। कोटद्वार में लगातार बढ़ रही इस तरह की गतिविधियों के बाद सरकारी सिस्टम पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं।

आईपीसी की धारा 274, 275, 420 इम कट्टील एक्ट 17 वी 17 सी आर डब्ल्यू 27 सी में मुकदमा दर्ज है। कोटद्वार फैक्ट्री में नकली दवा बरामद होने के बाद फैक्ट्री स्वामी विशद व रूडकी निवासी सचिन को गिरफ्तार किया गया है। बताया कि सचिन फैक्ट्री से माल उठाकर इसे आगे सप्लाइ करता था। बताया कि फैक्ट्री से 43 लाख रुपये की नकली दवा मिली है। फैक्ट्री में नकली दवा बनाकर उस पर बड़ी कंपनियों के रेपर लगाए जाते थे।

### जरूरतमंद मतदाताओं को मतदान के लिए मिलेगी मदद

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : यदि आप दिव्यांगजन हैं और लोकसभा चुनाव में मतदान करने में कोई दिक्कत हो रही है, तो चिंता होने की जरूरत नहीं है। सक्षम एप आपको मतदान केंद्र तक पहुंचाने में मदद करेगा। इसके लिए बस आपको मोबाइल फोन में सक्षम एप डाउनलोड कर अपनी जरूरत बतानी होगी। निर्वाचन कर्मी मतदान के दिन जरूरत के मुताबिक सहायता मुहैया कराएंगे।

भारत निर्वाचन आयोग ने दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा के लिए सक्षम एप जारी किया है। इसके लिए दिव्यांगजन अपने मोबाइल फोन में इस एप को डाउनलोड कर सकते हैं। यह एप मतदाता पंजीकरण से लेकर मतदान के दिन घर से लाने व छोड़ने की सुविधा उपलब्ध कराता है। एप की सुविधा लेने के लिए ओटीपी भेजा जाएगा। इस एप से दिव्यांग मतदाता वार तरह की सेवाएं पंजीकरण, सुविधाएं, खोज और सूचना व शिकायत संबंधी सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी/जिलाधिकारी डॉ. आशीष चौहान ने बताया कि पंजीकरण टैब के माध्यम से संबंधित व्यक्ति पंजीकरण, नाम जोड़ने या हटाने का विकल्प भर सकते हैं। सुविधाएं टैब के माध्यम से दिव्यांग मतदाताओं के लिए विभिन्न सुविधाओं के बारे में जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त वह मतदान केंद्र पर ढील वेयर, फिक एड ग्लॉब और अन्य सहायता के लिए अनुरोध कर सकते हैं।

## संगठन को मजबूत बनाने का लिया संकल्प



कोटद्वार में भाजपा की सदस्यता लेते युवा

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : भाजपा कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने संगठन को मजबूती के लिए कार्य करने का संकल्प लिया है। इस दौरान कांग्रेस के सेकड़ों कार्यकर्ता व पदाधिकारियों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। लालपानी क्षेत्र के वार्ड नंबर तीन में भारतीय जनता पार्टी की बैठक आयोजित

की गई। जिलाध्यक्ष वीरेंद्र सिंह रावत ने कहा कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में लगातार विकास कर रही है। पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीणों को मूलभूत सुविधाएं मुहैया करवाई जा रही हैं। हर घर जल, किसान सम्मान निधि, गौर देवी कन्या धन योजना, उच्चला योजना, आयुष्मान भारत जैसी कई कल्याणकारी योजनाओं

का जनता को बेहतर लाभ मिल रहा है। इस मौके पर जिला उपाध्यक्ष संजय भंडारी, विजय रावत, सूरज कुमार, कुलदीप कुमार, खुशहाल, वीरेंद्र सिंह, मोतीराम, सोहन लाल, जगमोहन सिंह, उमेश सिंह, मनोज कुमार, विनीता देवी, कमला देवी, मोनिका देवी, ममता देवी, सुमन देवी आदि मौजूद रहे।

## ठगी के फरार आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : मैट्रीमोनल साइड्स पर शादी का झांका देकर ठगी करने वाले फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। फरार आरोपी पर करीब ढाई हजार रुपये का इनाम भी रखा गया था। दो फरवरी 2022 को खुनीबड़ निवासी रघुवीर सिंह ने पुलिस को तहरीर दी थी। जिसमें उन्होंने बताया कि मैट्रीमोनल साइट्स पर शादी के विज्ञापन के नाम पर उनके साथ लाखों की ठगी की गई है। उन्होंने बताया था कि साइट पर अनुश्री किशोर रामराज नाम की महिला ने उनकी



पुलिस हिरासत में ठगी का आरोपी

प्रोफाइल पर एक प्रस्ताव भेजा, जिसे उन्होंने स्वीकार किया। इसके बाद सोशल मीडिया के मध्य से उनसे संपर्क किया गया। बताया कि इस दौरान उनसे विदेशी मुद्रा को

भारतीय करेंसी में ट्रांसफर करने के लिए धनराशि देने को कहा गया। जिसके बाद उन्होंने चार खातों में अलग-अलग धनराशि ट्रांसफर की। पुलिस ने बताया कि रघुवीर से करीब तीन लाख तीस हजार की धनराशि ठगी गई। पुलिस ने वीते आठ जनवरी को मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया था। जबकि ग्राम जसोला, बिहार निवासी अजय फरार चल रहा था। पुलिस ने गुरुवार को फरार आरोपी को भी गिरफ्तार कर जेल

### लोकसभा चुनाव को लेकर पुलिस ने कसी कमर, कौडिया में चलाया तलाशी अभियान

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कोटद्वार व बिजनौर पुलिस ने सख्ती दिखाया शुरू कर दिया है। दोनों जगहों की पुलिस ने संयुक्त रूप से उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कौड़िया चैक पोस्ट पर वाहन तलाशी अभियान चलाया। इस दौरान आमजन से भी कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग की अपील की गई।



कोटद्वार में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की सीमा पर स्थित कौड़िया चैक पोस्ट में अभियान चलाती पुलिस

कुछ दिन पूर्व पौड़ी व बिजनौर के उच्चाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें लोकसभा चुनाव को लेकर संयुक्त रूप से कार्य करने का निर्णय लिया गया था। इसके तहत बुधवार

देर शाम से उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड पुलिस ने संयुक्त रूप से कौड़िया चैक

की ओर आने वाले दोपहिया व चार पहिया वाहनों की तलाशी ली गई। वाहन से संबंधित दस्तावेज सामान के संबंध में गंभीरता से पृष्ठछाछ की जा रही थी। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक मण्डीपूषण श्रीवास्तव ने बताया कि लोकसभा चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनी रहे। इसके लिए गंभीरता से कार्य किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश व उत्तराखंड की पुलिस सीमा से सटे इलाकों में भी संयुक्त रूप से गश्त कर रही है। सीमा से गुजरने वाले प्रत्येक वाहन का नंबर भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है। बिजनौर की ओर से कोटद्वार

वाले प्रत्येक वाहन का नंबर भी रजिस्टर में दर्ज किया जा रहा है।

### सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका नाम भूलवश MAHISHI AGARWAL भूलवश अंकित हो गया है। जबकि मेरी पुत्री का सही व वास्तविक नाम मीताक्षी अग्रवाल MITAKSHI AGARWAL है। अतः मेरी पुत्री के जन्म प्रमाण पत्र में उसका सही व वास्तविक नाम मीताक्षी अग्रवाल MITAKSHI AGARWAL अंकित कर जन्म प्रमाण पत्र निगंत किया जाय।

विशु अग्रवाल पुत्र विनोद कुमार अग्रवाल निवासी गोविन्द नगर काशीरामपुर, तहसील कोटद्वार, जिला पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड। (1666/21)

### बैरियरों पर चौकसी बरतें : एसएसपी

पौड़ी : बरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्वेता चौबे ने कोतवाली पौड़ी का निरीक्षण करते हुए हर फ्लायडी की शिकायत सुनते हुए उनका पूरा पता और रजिस्टर में फ्रीडबैक का काम बनाने को कहा। उन्होंने लोकसभा चुनावों को देखते हुए प्रभारी निरीक्षक एनके भट्ट को थाना क्षेत्र में पड़ने वाले सभी बैरियरों पर चौकसी बरतने और चुनाव को प्रभावित करने वाली गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए एसएसपी ने बैरियों का निरीक्षण करते हुए ने पुराने भवनों की मरम्मत, मैस के बर्तनों के लिए जवद प्रस्ताव भेजने के निर्देश दिए। इस दौरान एसएसपी ने पुलिस जवानों से शस्त्रों का अभ्यास भी कराया। उन्होंने थाने में रखे आपदा उपकरणों को हर समय तैयार हालात में रखने, कोर्ट से निस्तारित हो चुके लावारिस वाहनों का जल्द निस्तारण करने, समय-समय पर अपने थाना क्षेत्र के दूरस्थ गांवों में जाकर महिलाओं, बच्चों, बुजुर्गों को अपराधों, साइबर अपराधों आदि को लेकर जागरूक करने, शत फीसदी सत्यापन करने, आगामी लोक सभा चुनावों के तहत सतर्कता बरतने के निर्देश दिए।

## रंगोली में साहित्य, मेहंदी प्रतियोगिता में स्वाती और सविता ने बाजी मारी

### आईएचएमएस में लोकसभा चुनाव को लेकर आयोजित की गई प्रतियोगिताएं

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : इंस्टीट्यूट ऑफ हास्पिटैलिटी मैनेजमेंट एंड साइंसेज (आईएचएमएस) में लोकसभा चुनाव-2024 के तहत रंगोली, मेहंदी और नाटक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। जिसमें संस्थान के छात्र-छात्राओं ने अपनी प्रतिभा के माध्यम से शत प्रतिशत मतदान का संदेश दिया। बलभद्रपुर बीईएल रोड स्थित संस्थान परिसर में आयोजित प्रतियोगिता का संस्थान के एमडी वीएस नेगी ने शुभारंभ किया। उन्होंने छात्र-छात्राओं से आगामी लोकसभा चुनाव में अपने मताधिकार का प्रयोग करने की अपील की। इस अवसर पर छात्र-छात्राओं ने पांच ग्रुप में रंगोली बनाई, जिसमें उन्होंने वोट, प्रजातंत्र, मेरा वोट मेरा अधिकार समेत अनेक श्लोकान खिली हुई रंगोली बनाई। मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने मतदान संबंधी मेहंदी सजाई, वहीं नाटक में छात्रों ने मतदान करने के फायदे गिनाए। संयोजक सपना रौथाना के मार्गदर्शन में आयोजित प्रतियोगिताओं में निर्णायकों द्वारा दिए गए अंकों के आधार पर



आयोजित प्रतियोगिता में प्रतिभाग करते विद्यार्थी

मेहंदी प्रतियोगिता में स्वाती-सविता ने प्रथम, दिव्या नेगी-ममता, प्रदीप भट्ट, नवीन किशोर, टकचंद्र कुंवर, आशुतोष धर द्विवेदी, अनुज नेगी, अनिल यादव, अजय आचार्य आदि मौजूद रहे।

### कार्यालय :- नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल) ।।

पत्रांक :-	4989 /कर अंश/भवन/2023-24	दिनांक :-	27/02/2024	
<b>सार्वजनिक सूचना</b>				
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि निम्न व्यक्ति/व्यक्तियों द्वारा नगर निगम कोटद्वार के भवन कर अभिलेखों पूर्व भवन स्वामी के स्थान पर अपना नाम दर्ज करने हेतु स्वामित्व प्रमाण पत्रों एवं शपथ पत्र आदि के आधार पर आवेदन किया गया है। अतः नगर निगम अधिनियम-1959 की धारा 213(ख) के अन्तर्गत समस्त प्रभावित व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि जिस किसी को निम्न नामान्तरण/नामान्तरणों पर आपत्ति हो वह मय साक्ष्यों को उपरोक्त सार्वजनिक सूचना के प्रकाशन की तिथि से 30 दिवस भीतर आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है। मियाद समाप्त होने पर उपलब्ध अभिलेखिता साक्ष्यों के आधार पर सम्पत्ति के नामान्तरण हेतु निर्णय पारित कर लिये जायेंगे।				
क्र० सं०	सम्पत्ति संख्या एवं मॉहल्ला/वार्ड का नाम	भवन कर अभिलेखों में दर्ज नाम (नाम जो निरस्त होना है)	आवेदक का नाम व पता (नाम जो दर्ज होना है)	सम्पत्ति का स्वामित्व प्राप्त करने का आधार
1	2	3	4	5
1	17/15 वार्ड नं० 15 मालगोवम रोड	श्री भगवती चरण अग्रवाल स्व० श्री हारिका प्रसाद अग्रवाल	श्री गोपालकृष्ण अग्रवाल, श्री महेश चन्द्र अग्रवाल, रविशंकर अग्रवाल एवं श्रीमती विमला देवी पुत्रगण/पत्नी स्व० श्री भगवतीचरण अग्रवाल	मूल्य प्रमाण पत्र, उत्तर-नौवीं प्रमाण पत्र, एवं शपथ पत्र
सहायक नगर आयुक्त				
नगर निगम कण्वनगरी कोटद्वार।				
(1667/51)				

## पोस्टर प्रतियोगिता में पिया ने मारी बाजी



आयोजित प्रतियोगिता में भाग लेते विद्यार्थी

### पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में आयोजित की गई कार्यशाला

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : विज्ञान दिवस पर पब्लिक इंटर कॉलेज सुरखेत में युसर्क विज्ञान चेतना केंद्र की ओर से प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इस दौरान पोस्टर प्रतियोगिता में पिया रावत ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। कार्यक्रम में महान भौतिक पौड़ी में जनाक्रोश रेली सात मार्च को जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : संयुक्त संघर्ष समिति द्वारा शहर की विभिन्न समस्तियों के हल की मांग को लेकर 7 मार्च को एक बार फिर से जनाक्रोश रेली निकाली जाएगी। समिति के सदस्यों ने आरोप लगाया कि प्रशासन शहर की समस्याएं हल करने को लेकर गंभीर नजर नहीं आ रहा है। जिसके चलते 7 मार्च को जनाक्रोश रेली निकाली जाएगी। मुख्यार को रामलीला मैदान में संयुक्त संघर्ष समिति की कोर कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। समिति के मीडिया प्रभारी अखिलेश नेगी ने बताया कि संयुक्त संघर्ष समिति कुछ निस्तारण, जिला अस्पताल को पीपीपी मॉड से हटाने, गड्डा मुक्त सड़के सहित विभिन्न मांगों के हल को लेकर आंदोलनरहित है। कहा कि बीते बुधवार को जिला प्रशासन के साथ बैठक भी आयोजित की गई लेकिन जिला प्रशासन शहर की समस्याओं के हल को लेकर गंभीर नजर नहीं आया। बताया कि मुख्यार को समिति की कोर कमेटी की बैठक में 7 मार्च को जनाक्रोश रेली निकालने का निर्णय लिया गया है। बैठक में समिति के अध्यक्ष मनोज रावत, सहसंयोजक कुलदीप गुसाईं, निखिल रौथाना आदि शामिल रहे।

विज्ञानी डा. चन्द्रशेखर वेंकट रमन द्वारा की गई उल्लेख वैज्ञानिक खोज के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी दी गई। प्रधानाचार्य पुष्कर सिंह नेगी ने छात्र-छात्राओं को बताया कि प्रति वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसी दिन 1928 को हमारे देश के महान भौतिक शास्त्री डा. चन्द्रशेखर वेंकट रमन द्वारा एक उल्लेख वैज्ञानिक खोज की गयी थी, जिसे रमन प्रभाव के नाम से जाना जाता है। इस

### चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए 1200 हेल्थ किट तैयार

जयन्त प्रतिनिधि। पौड़ी : लोकसभा चुनावों को लेकर स्वास्थ्य महकमे ने भी अपनी तैयारियां की है। जिले में अब तक जहां स्वीप गतिविधियों को लेकर विभाग ने कंट्रोल रूम शुरू किया है वहीं चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों के लिए 1200 हेल्थ किट तैयार हो गई है। अधिकारियों के अनुसार ये हेल्थ किट हर बुथ भेजी जाएगी। पौड़ी के सीएमओ डॉ. प्रवीण कुमार ने बताया कि आयोग की एसओपी के तहत काम शुरू किया गया है। इसके लिए एक नोडल अफसर भी तैनात किया गया है। स्वीप गतिविधियों को लेकर ब्लॉक वार एनएमएस सेंटरों की लिस्ट बनाई जा रही है। इनमें जल्द ही वोटर जागरूकता कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। वहीं नोडल अफसर डॉ. एसडी वर्मन के मुताबिक चुनाव ड्यूटी में तैनात सुरक्षा कार्मिकों के साथ ही अन्य कार्मिकों को हेल्थ संबंधी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेली एवं वीडियो कंसल्टेशन सेंटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पौड़ी में प्रस्तावित कर दिए हैं। हर सेंटर पर कम से कम मय स्टॉफ के 4 डॉक्टर तैनात रहेंगे। जो हेल्थ किट बनाकर तैयार की गई है उनमें 1200 किट बना दी गई है। जो चुनाव किट को हर बुथ भेजी जाएगी। इन हेल्थ किटों में सभी आवश्यक दवाइयां रखी गई है।

इसके साथ ही 108 सेवा को भी जोड़ा जा रहा है। इसमें किस वृथ से कितना समय संबंधित पास के स्वास्थ्य केंद्र तक पहुंचने में लगेगा इसके लेकर भी खाका खींचा जा रहा है। पोलिंग वृथ तक चुनाव ड्यूटी में तैनात कार्मिकों को हेल्थ संबंधी सुविधाओं के लिए स्वास्थ्य विभाग ने टेली एवं वीडियो कंसल्टेशन सेंटर श्रीनगर मेडिकल कॉलेज और जिला अस्पताल पौड़ी में प्रस्तावित कर दिए हैं। हर सेंटर पर कम से कम मय स्टॉफ के 4 डॉक्टर तैनात रहेंगे। जो हेल्थ किट बनाकर तैयार की गई है उनमें 1200 किट बना दी गई है। जो चुनाव किट को हर बुथ भेजी जाएगी। इन हेल्थ किटों में सभी आवश्यक दवाइयां रखी गई है।

## "संपत्ति/भवनकर उपविधि—2023-24" आंशिक संशोधन सूचना

इस कार्यालय के पत्रांक 365 /उप0वि0भवन/सम्पत्तिकर/2023-24 दिनांक: 04 दिसम्बर, 2023 से नगर पंचायत सतपुली द्वारा "संपत्ति/भवनकर उपविधि-2023-24" जो नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इस उपविधि का प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित की गई थी व दिनांक 06 दिसम्बर, 2023 के दैनिक हिन्दुस्तान समाचार पत्र में प्रकाशित हुई है, के बिन्दु संख्या 3 वार्षिक मूल्यांकन 3 के (क) (ख) एवं (ग) को हटाते हुये उसके स्थान पर उत्तराखण्ड शासन विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग की अधिसूचना संख्या 127/XXXVI (3)/2021/27(1)/2021 देहरादून, 12 अप्रैल, 2021 द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिपेक्ष्य में अंग्रेज संशोधन के द्वारा उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम-1916 (अनुकूलन एवं उपांतरण आदेश, 2002) (जिसे इसके आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 140 निम्नलिखित रूप से प्रतिस्थापित की गई है के अनुसार अनुसार "संपत्ति/भवनकर उपविधि-2023-24" ने निम्न आंशिक संशोधन किया गया है, एवं नगर पालिका अधिनियम-1916 की धारा-301(1) के अन्तर्गत जनसामान्य एवं जिन पर इसका प्रभाव पड़ने वाला है उनसे आपत्ति एवं सुझाव हेतु प्रकाशित किया जा रहा है। अतः समाचार पत्र में उक्त "आंशिक संशोधन सूचना के प्रकाशन से दिनांक 08 जनवरी, 2024 तक लिखित सुझाव एवं आपत्तियां अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत, सतपुली, जनपद-पौड़ी गढ़वाल (उत्तराखण्ड) को प्रेषित की जा सकेंगी। वाद मियाद प्राप्त आपत्तियां एवं सुझावों पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। 3- वार्षिक मूल्यांकन:-"भवन या भूमि या दोनों, जैसी भी स्थिति हो, का पूंजीगत मूल्य, जो कि भवन के आच्छादित क्षेत्रफल या भूमि के क्षेत्रफल या दोनों, जैसी भी स्थिति, को भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 के प्रायोजनार्थ कलेक्टर द्वारा निर्धारित सर्किल रेट/निर्माण की दर जो प्रचलन में हो, से गुणा करने पर प्राप्त मूल्य; किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सम्पत्ति कर के अन्तर्गत सामान्य कर की दर वार्षिक मूल्य के 0.01 प्रतिशत से 1 प्रतिशत के मध्य होगी तथा पूंजीगत मूल्य आधारित सम्पत्ति कर प्रारम्भ होने के अगामी 5 वर्षों में किसी भी दशा में ठीक पूर्व के वर्ष में निर्धारित कर से कम अथवा 5 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा, तत्पश्चात अनुवर्ती वर्षों में सम्पत्ति कर में प्रतिवर्ष वृद्धि की अधिकतम दर नियमावली में विहित रीति से तय की जायेगी; परन्तु यह भी कि पूंजीगत मूल्य आधारित कर का निर्धारण प्रत्येक वर्ष में एक बार किया जायेगा तथा एक अप्रैल को प्रचलित सर्किल रेट के आधार पर ही पूर्ण वर्ष का सम्पत्ति कर निर्धारित किया जायेगा।" (भवन का वार्षिक मूल्य = आच्छादित क्षेत्रफल \* गणना वर्ष को लागू प्रतिवर्ग मीटर सर्किल रेट)

आवासीय भवनों के लिए गणना निम्न भांति की जाएगी:-	
i आवासीय भवनों / विभागीय आवास के लिए वार्षिक मूल्यांकन के	0.01 प्रतिशत
ii आवासीय भवन, जिनमें परिवार किराये पर निवासरत हैं के लिए वार्षिक मूल्यांकन (वार्षिक किराया) के	1.00 प्रतिशत
<b>अनावासीय भवनों के लिए गणना निम्न भांति की जाएगी:-</b>	
i सरकारी कार्यालय भवनों के लिए वार्षिक मूल्यांकन के	0.012 प्रतिशत
ii व्यवसायिक प्रतिष्ठानों/दुकानों के लिए वार्षिक मूल्यांकन के	0.015 प्रतिशत
iii वेडिंग प्वाइंट/होमस्टे/होटल 01 कमरे से 10 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.025 प्रतिशत
iv होटल 10 कमरे से 35 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.050 प्रतिशत
v होटल 35 कमरे से 50 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.075 प्रतिशत
vi होटल 35 कमरे से 50 कमरे का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.10 प्रतिशत
vii जिस अवासीय मकान/भूमि पर मोबाइल पर टावर का निर्धारण वार्षिक मूल्यांकन के	0.075 प्रतिशत
अधिशासी अधिकारी	प्रशासक
नगर पंचायत सतपुली	नगर पंचायत सतपुली
	/उपजिलाधिकारी सतपुली
(1668/65)	

## शहर में निकाली मनमोहक झांकी

जयन्त प्रतिनिधि। कोटद्वार : प्रजापिता ब्रह्माकुमारीज ईश्वरीय विवि की नजीबाबाद रोड, मिश्रा कालोनी स्थित स्थानीय शाखा की ओर से वर्तमान में महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में नगर निगम के विभिन्न क्षेत्रों में शिव संदेश यात्रा निकाली जा रही है। इसी क्रम में शाखा की ओर से गुरुवार को भाबर क्षेत्र के जीवानन्दपुर में शिव संदेश यात्रा निकाली गई। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में वी के ज्योति बहन ने कहा कि परमात्मा सर्व शक्तिमान है। उनका धरती पर अवतरण दिव्य जन्म के माध्यम से होता है। कहा कि शिव हमेशा ही कल्याणकारी रहे हैं। उनकी आराधना कर हम उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। स्थानीय निवर्तमान पार्षद कमल नेगी ने कहा कि आज का मानव दिशाहीन जीवन जी रहा



शहर में निकाली गई झांकी

है। ऐसे में ब्रह्माकुमारीज ज्ञान गंगा जीवन को बेहतर दिशा देने का कार्य कर रही है। इस अवसर पर विभिन्न केंद्रों के ब्रह्माकुमारी भाई बहन और स्थानीय लोग मौजूद रहे।

# ऊर्जा से विकास की गति को बढ़ाएंगे धामी

## धामी के नेतृत्व में वैश्विक निवेशक सम्मेलन में ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे अधिक 1.03 लाख करोड़ के 157 करार

देहरादून। दशकों से बिजली के आपूर्ति और मांग के बीच की बढ़ते अंतर से त्रस्त उत्तराखंड अब ऊर्जा प्रदेश में बदल रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड को ऊर्जा क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए एक के बाद एक कई बड़े कदम उठाए हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देशन में उत्तराखण्ड की जल विद्युत परियोजनाओं के कार्य में गति लाकर ऊर्जा उत्पादन के नये कीर्तिमान बनाकर उत्तराखंड ने अर्थव्यवस्था को नये आयाम देने की रणनीति अपनाई है। राज्य में अभी कुल आवश्यकता का 35 से 40 प्रतिशत तक ऊर्जा का उत्पादन होता है। आपूर्ति बरकरार रखने के लिए उत्तराखंड को शेष बिजली सेंट्रल जनरेटिंग स्टेशन (सी.एस.) या खुले बाजार से खरीदनी

पड़ती है। इसकी दर अधिक होती है। राज्य में बेस लोड 1750 मेगावाट की आवश्यकता है। इसमें मौसम के अनुसार परिवर्तन होता रहता है। गर्मियों में यह 2400 मेगावाट तक पहुंच जाती है और सर्दियों में 2500 मेगावाट तक।

मुख्यमंत्री श्री धामी के सतत प्रयासों के कारण मांग और आपूर्ति के बीच का अंतर 450 मेगावाट का अंतर होने के बावजूद वर्ष 22-23 में पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में 23 घंटे 36 मिनट और ग्रामीण इलाकों में 23 घंटे 15 मिनट बिजली की आपूर्ति की गई। इस बीच वर्ष 2023 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर बिजली-सौभाग्य योजना के अन्तर्गत ढाई लाख घरों का विद्युतीकरण किया गया। उत्तराखंड में बिजली उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी



वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेशकों को लुभाने में अक्ल रहा ऊर्जा विभाग

प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चयनित फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य निर्धारित किया था। इसके आधार पर सरकार ने 2.50 लाख करोड़ रुपये निवेश पर एमओयू का लक्ष्य रखा, लेकिन सरकार को लक्ष्य से एक लाख करोड़ अधिक निवेश पर करार करने में कामयाबी मिली। उत्तराखंड में निवेश करने के लिए देश-दुनिया के निवेशकों को लुभाने में ऊर्जा विभाग अक्ल रहा। सोलर ऊर्जा क्षेत्र में सबसे

अधिक 1.03 लाख करोड़ रुपये के 157 प्रस्ताव पर एमओयू किए गए, जबकि उद्योग विभाग दूसरे और पर्यटन तीसरे स्थान पर रहा। वैश्विक निवेशक सम्मेलन में कुल 1,779 प्रस्ताव पर 3.56 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश पर करार हुआ है। इसमें 44 हजार करोड़ रुपये निवेश की ग्राउंडिंग की जा चुकी है। प्रदेश सरकार ने आठ और नौ दिसंबर को आयोजित वैश्विक निवेशक सम्मेलन में निवेश के लिए चयनित फोकस सेक्टर के संबंधित विभागों को एमओयू का लक्ष्य निर्धारित किया था।

ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त करते हुए लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना का कार्य शुरू कराने को महत्वपूर्ण उपलब्धि बताया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि देहरादून के लोहारी गांव के पास बनने वाली इस परियोजना से उत्तराखंड के साथ ही उत्तर प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को पेयजल और सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। इसके साथ ही उत्तराखंड को 300 मेगावाट बिजली प्राप्त होगी और बाढ़ों पर नियंत्रण रखा जा सकेगा

उन्होंने राज्य में आने वाले उद्योगों की आवश्यकताओं के मद्देनजर जल विद्युत उत्पादन बढ़ाने के लिए कार्य करने और वर्ष 2030 तक इसे 2200 मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। वर्ष 2022 में 120 मेगावाट की व्यापी परियोजना उत्पादन शुरू

कर देगी। लखवाड़ परियोजना और विश्वास दिलाती है कि इस राज्य में ऊर्जा की सहज और निरंतर उपलब्धता विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में जिस तरह दुनिया भर के उद्योग जगत ने उत्तराखंड में निवेश करने और औद्योगिक इकाइयों लगाने में रुचि ली है, यह ऊर्जा क्षेत्र में मिली सफलताओं और नई पहल से भी जुड़ा है, जो विश्वास दिलाती है कि इस राज्य में ऊर्जा की सहज और निरंतर उपलब्धता विकास के नये कीर्तिमान स्थापित करेगी।

माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का होगा। उनके इस वाक्य ने उत्तराखंडवासियों में नई ऊर्जा और उत्साह का संचार किया है। केन्द्र सरकार से राज्य को प्रत्येक क्षेत्र में अभूतपूर्व सहयोग मिल रहा है। राज्य सरकार सरलिकरण, समाधान, निस्तारण और जनसंतुष्टि के मूलमंत्र पर चलते हुए अंत्योदय की भावना के साथ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के विकास, कल्याण और उन्नति के लिए निरंतर प्रयासरत है। हम वर्ष 2025 तक देवभूमि को देश का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

पुष्कर सिंह धामी, मुख्यमंत्री, उत्तराखंड

जल विद्युत परियोजना: अपार संभावनाएं हैं देवभूमि में

देहरादून। गंगा और यमुना के मायके उत्तराखंड में जल विद्युत परियोजनाओं के लिए अपार संभावनाएं हैं। सरकारी और गैर सरकारी उपक्रम इस राज्य में ऐसी कई योजनाओं पर कार्य कर रहे हैं। राज्य में ऐसी काफी नदियां हैं जो जल विद्युत के रूप में समृद्धि और विकास की सीमा तक ला सकती हैं। उत्तराखंड की नदियों में जलविद्युत उत्पादन की असीमित संभावनाएं हैं। ऐसी नदियों में अलकनंदा, भिलंगना, पिंडर, मंदाकिनी, कैलगंगा, बाल गंगा, सुवारी गाड, धौलीगंगा, भागीरथी, भ्यूंदर, खिराओगंगा, धरम गंगा, कल्पगंगा भी शामिल हैं।

## सौर ऊर्जा से हर गांव पहुंचेगी समृद्धि, घर के समीप रोजगार

देहरादून। उत्तराखंड ने सौर ऊर्जा से विकास की राह प्रशस्त करने और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसरों के सृजन की दिशा में कई बड़े और क्रान्तिकारी कदम बढ़ा दिये हैं। राज्य को विकास की डगर पर तेजी से आगे बढ़ाने की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की यह पहल राज्य के शहरी क्षेत्रों के साथ ही दूरदराज के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए समृद्धि और आत्मनिर्भरता का वरदान बन सकती है।

पर्यावरण को कोई नुकसान पहुंचाए बिना गांव और कस्बों में भी बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसरों के सृजन और राज्य की बिजली की आवश्यकता को पूरा करने वाली यह नई रणनीति मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सौर ऊर्जा नीति के रूप में उपहार की तरह दी है। सौर ऊर्जा नीति-2023 बनाकर राज्य में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य लेकर तेजी से कार्य आरम्भ कर दिया गया है। वर्ष 2027 तक यह लक्ष्य पूर्ण किया जाना है। राज्य को हरित ऊर्जा के माध्यम से खुशियों से संवारने की यह योजना सरकार की नई सोच और समय के साथ कदमताल करते हुए बड़े लक्ष्य प्राप्त करने की कार्ययोजना से जुड़ी है। मुख्यमंत्री श्री धामी ने इस नीति को विकास और रोजगार से जोड़ने के लिए यह प्रावधान किया है कि सौर ऊर्जा उत्पादन के प्रोजेक्ट निजी या सरकारी भूमि लीज पर लेकर लगाये जा सकते हैं। सरकारी भूमि पर ये प्रोजेक्ट लगाने पर उनमें 70 प्रतिशत रोजगार स्थानीय युवाओं

उत्तराखंड में 2500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन की पहल

सौर नीति 2023 (प्रोत्साहन)

पूंजीगत सब्सिडी

परियोजना श्रेणियां	क्षमता (केडब्लू)	राज्य सब्सिडी (आईएनआर/केडब्लू)
रुफटॉप सौर	0-1	23000
	1-3	17000
सामुदायिक सौर	5-500	8000
सौर ग्राम	50-200	15000
बिहाइन्ड द मीटर (ऊर्जा भंडारण के साथ)	<1 केडब्लू	23000 (भंडारण के बिना) 28000 (भंडारण के साथ)

को देने की अनिवार्यता निर्धारित कर दी गई है। सौर ऊर्जा उत्पादन की परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने की उद्देश्य में सिंगल विंडो व्यवस्था और लैंड यूज परिवर्तन, रजिस्ट्रेशन, विकास शुल्क आदि में छूट देने का भी निर्णय किया गया है। राज्य की ऊर्जा की आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए हर

साल महंगी बिजली खरीदने वाले ऊर्जा निगम को भी इस नई नीति से उत्तराखंड में ही सस्ती दर पर बिजली मिल सकती है। सौर ऊर्जा के लिए राज्य में निवेश करने वालों से बिजली क्रय करना ऊर्जा निगम के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। इससे निवेशकों का जोखिम कम हो जाएगा। उत्तराखंड सरकार की यह

सशक्त हुआ पारेषण तंत्र

- पिटकुल को रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट ने ए-प्लस की क्रेडिट रेटिंग दी, जिससे पिटकुल को ऋण में 0.25 प्रतिशत की छूट मिल रही है। उपभोक्ताओं को टैरिफ में यह छूट प्रदान की जा रही है।
- बहुप्रतीक्षित 220 केवी रुद्रपुर-जाफरपुर ट्रांसमिशन रेल लाइन को इस वर्ष मई में ऊर्जाकृत किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस लाइन का लोकार्पण किया।
- दो टावरों के बीच प्रदेश में सबसे लंबे स्पान के साथ पिटकुल ने पारेषण लाइन का निर्माण किया। इसमें विशेष तकनीकी का प्रयोग कर ऊर्जा के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल की।
- देहरादून में 132 केवी बिंदाल-पुरकल लाइन के स्थापना को लेकर तेजी से कदम आगे बढ़ रहे हैं। टावर के लिए स्थान चयनित कर लिया गया है।

पहल राज्य में औद्योगिक विकास की गति तेज करने, युवाओं को अपने घर के पास रोजगार के अवसर देने और प्रदेश में चौबिस घंटे लगातार विद्युत आपूर्ति की दिशा में बहुत प्रभावी निर्णय है। इससे ग्लोबल वार्मिंग और जलवायु परिवर्तन के खतरों को कम करने में भी मदद मिलेगी।



## ऊर्जा

ऊर्जा के लिहाज से वर्ष 2023 उत्तराखंड के लिए उपलब्धियों भरा रहा। सरकार और ऊर्जा निगम के प्रयासों ने इस वर्ष ऊर्जा प्रदेश के संकल्प को नई दिशा दी। उपभोक्ता सेवा रेटिंग में उत्तराखंड ने हिमालयी राज्यों में प्रथम स्थान प्राप्त किया। यह संभव हो पाया प्रदेश में विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में व्यापक सुधार के साथ ही उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए उठाए जा रहे प्रभावी कदमों से। निर्बाध और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति के लिए प्रदेश में नए सब स्टेशनों के निर्माण के साथ पुरानों का उच्चिकरण युद्धस्तर पर किया जा रहा है। साथ ही बिलिंग और मीटरिंग में सुधार लाने के प्रयास भी जारी हैं। नए वर्ष में एडीबी वित्त पोषित स्मार्ट प्रीपेड मीटर और भूमिगत विद्युत लाइन परियोजनाओं के धरातल पर उतरने की उम्मीद है।

## विद्युत उत्पादन आत्मनिर्भर बनने की तैयारी



देहरादून। उत्तराखंड ऊर्जा के क्षेत्र में अपार संभावनाओं से भरा राज्य है। हमारी कई सार्वजनिक बिजली परियोजनाएं सफलतापूर्वक संचालित की जा रही हैं।

हम राज्य में सौर ऊर्जा, जल विद्युत और कोयले से बिजली उत्पादन की दीर्घकालिक योजना पर काम कर रहे हैं। उत्तराखंड को ऊर्जा प्रदेश बनाने में सौर ऊर्जा का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा।

उत्तराखंड ऊर्जा उत्पादन के लिए प्राकृतिक नवीकरणीय संसाधनों से संपन्न है। इसमें कई सूक्ष्म जलवायु क्षेत्र हैं। पहाड़ी क्षेत्र ठंडे और धूप वाले और ठंडे और बादल वाले जलवायु क्षेत्रों के करीब हैं, जबकि कुछ स्थान जैसे देहरादून अर्ध-मध्यम जलवायु क्षेत्रों के अंतर्गत आता है। इसके अलावा,

हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर और रुद्रपुर के मैदानी इलाके मिश्रित जलवायु क्षेत्र में स्थित हैं। इसके अलावा, राज्य में नदियों और नहरों का एक बड़ा नेटवर्क है जो बिजली उत्पादन की अपार संभावनाएं प्रदान करता है। हाल ही में राज्य कैबिनेट द्वारा उत्तराखंड पंप स्टोरेज परियोजना नीति को मंजूरी दी गई थी। उसके लिए पंप भंडारण परियोजनाएं विकसित की जाएंगी।

बढ़ती मांग के अनुसार बिजली की सुचारु आपूर्ति। राज्य के भीतर केंद्र और राज्य सरकार के उपक्रमों की बांध आधारित जलविद्युत परियोजनाओं में जल भंडारण क्षमता बढ़ाई जाएगी। इस नीति ने 1000 मेगावाट से 5000 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली उत्पादन का मार्ग प्रशस्त किया

है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से और उनके निर्देशन में उत्तराखंड जल संसाधनों का बहुत कुशलता से उपयोग कर रहा है और युवाओं के लिए रोजगार के नये अवसर खोल रहा है। राज्य में विकास की गति देखकर प्रधानमंत्री ने खुद कहा है कि राज्य की सरकार ने इस कहावत को बदल दिया है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम नहीं आती। ऊर्जा विभाग 24 गुणा 7 निरंतर बिजली प्रदान करने, हर घर को विद्युतीकृत करने और 100 प्रतिशत ग्रामीण विद्युतीकरण हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध है। ऊर्जा विभाग गांवों और बस्तियों के विद्युतीकरण के लिए बुनियादी ढांचे के निर्माण पर भी काम कर रहा है। इसका उद्देश्य राज्य को बिजली उत्पादन, पारेषण और वितरण

पर्यावरण के अनुकूल तरीके से स्वच्छ और हरित ऊर्जा का उपयोग करने के लिए भी काम कर रहे हैं।

हरित ऊर्जा के उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए श्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार ने नीति बनाकर राज्य में इस क्षेत्र में निवेश की नई राह प्रशस्त कर दी है। सौर ऊर्जा से औद्योगिक क्षेत्रों के साथ ही वाणिज्यिक और कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाई जा सकेगी।

यह आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरण की दृष्टि भी लाभप्रद होगा। गांवों की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और प्राकृतिक पारिस्थितिकी की सुरक्षा के लिए भी यह एक अच्छा प्रयास है।

वर्ष 2023 में ऊर्जा निगम की प्रमुख उपलब्धियां

- केंद्रीय विद्युत मंत्रालय से 'ए' रेटिंग के साथ देशभर के 51 डिक्राम में 12वां स्थान।
- देहरादून स्थित टेस्ट प्रयोगशाला को एनएबीएल सर्टिफिकेट से प्रमाणित किया गया।
- 12 एमवीए क्षमता के दो नए 33/11 केवी उपसंस्थानों व 70.78 किमी नई 33 केवी लाइन का निर्माण।
- विद्युत उत्पादन कंपनियों को समय पर भुगतान कर 100 करोड़ रुपये की बचत की।
- डिजिटल माध्यम से भुगतान 71 से बढ़कर 76 प्रतिशत हो गया।
- त्वरित गति से कार्य करने व बेहतर सुविधाओं के लिए फ्रील्ड एक्टिविटी मैनेजमेंट मोबाइल एप लॉन्च।
- नए विद्युत संयोजन देने के लिए उपभोक्ता स्वयं सेवा मोबाइल एप अपग्रेड।
- ग्रामीण क्षेत्रों में औसतन 23.22 घंटे और शहरी क्षेत्रों में 23.36 घंटे विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित।

यूजेवीएनएल की वर्ष 2023 की उपलब्धियां

- 1420.60 मेगावाट की 19 जल विद्युत परियोजनाओं से वार्षिक 5,433 मिलियन यूनिट का उत्पादन (पर्यावरणीय प्रवाह छोड़ते हुए) औसत टैरिफ मात्र रुपये 1.60 की दर से किया गया है।
- 300 मेगावाट की बहुउद्देशीय लखवाड़ परियोजना का कार्य प्रारंभ। इससे पांच राज्यों को पीने एवं सिंचाई के लिए जल की आपूर्ति के साथ उत्तराखंड में 300 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन हो सकेगा।
- छह बांध व बैराजों को सुदृढ़ करने और उनकी आयु बढ़ाने के लिए कार्य किए गए।
- प्रदेश भर में कई लघु जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गईं।
- 26 मेगावाट की सोलर परियोजना स्थापित की जा रही है मैदान से लेकर पहाड़ तक।
- आयु पूरी कर चुकी परियोजनाओं के सुरक्षित परिचालन को आरएमयू के कार्य गतिमान, जिससे उत्पादन 15 से 20 प्रतिशत बढ़ा।
- तिलोथ (90 मेगावाट) और ढालीपुर (51 मेगावाट) की मशीनों की मरम्मत।
- किसाऊ बहुउद्देशीय परियोजना (660 मेगावाट) के निर्माण के लिए डीपीआर गठित, परियोजना को मिली गति।

इन योजनाओं को धरातल पर उतारने का लक्ष्य

- कुमाऊ क्षेत्र में 120 मेगावाट की सिरकारीभोलव 114 मेगावाट की सेलाउथिंग जल विद्युत परियोजना पर कार्य शुरू करना।
- यमुना घाटी में 72 मेगावाट की ल्यूणी-प्लासू जल विद्युत परियोजना का कार्य शुरू करना। इसकी डीपीआर गठित कर ली गई है, भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया शेष।
- 81 मेगावाट की आराकोट-ल्यूणी जल विद्युत परियोजना की डीपीआर गठित करना।
- प्रदेश में 15.84 लाख स्मार्ट प्रीपेड मीटर की स्थापना की जानी है।

- हरिद्वार, रुड़की, काशीपुर, रुद्रपुर व हल्द्वानी में रकाडा का विस्तार।
- 33/11 केवी के 96 उपसंस्थानों का सुदृढ़ीकरण।
- 59,212 वितरण परिवर्तक व 2,602 फीडरों में स्मार्ट मीटरिंग की स्थापना।
- विद्युत व्यवस्था और सुदृढ़ करने को 396 नए वितरण परिवर्तकों (ट्रांसफार्मर) की स्थापना।
- देहरादून शहर में 243 किमी एचटी लाइन व 152 किमी एलटी लाइन को भूमिगत करना।
- हल्द्वानी शहर में 88 किमी व नैनीताल शहर में 19 किमी लाइन को भूमिगत करना।

# तीर्थारटन और पर्यटन से आर्थिकी संवारने का संकल्प

## विकास के पथ पर सधे कदम

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के मार्गदर्शन में उत्तराखण्ड के युवा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में भाजपा सरकार ने कई उपलब्धियां हासिल की हैं। सीमांत गांवों के लिए 51 वाइब्रेट विलेज का चयन हो या पर्यटन का क्षेत्र, राज्य ने प्रगति के पथ पर मजबूती से कदम बढ़ाए हैं। फिल्मकारों के पसंदीदा शूटिंग डेस्टिनेशन के रूप में पहचान स्थापित करने के साथ ही वैश्विक निवेशक सम्मेलन के जरिये उत्तराखंड ने इस वर्ष देश-दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। जी 20 सम्मेलन की कड़ी में तीन बैठकों की मेजबानी का अवसर मिलने के बाद राष्ट्रीय खेलों के आयोजन की जिम्मेदारी भी इसी वर्ष राज्य के हिस्से आई। नए वर्ष में उत्तराखंड देश में समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य बनने की दिशा में तेजी से बढ़ रहा है, जो उसकी नई पहचान बन सकता है।

देहरादून। उत्तराखंड राज्य देवभूमि के रूप में भी प्रसिद्ध है और पर्यटन भूमि के रूप में भी। हिमालय की चोटियों से लेकर घने जंगलों तक यह राज्य अपने अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य व अपने विश्व प्रसिद्ध धार्मिक स्थलों के कारण

विकास करने के कारण, पर्यटकों के लिए यहाँ पर आना तथा समय व्यतीत करना व यहां से तरोताजा होकर लौटना काफी सुलभ हो गया है। इसी कारण पिछले कुछ वर्षों में उत्तराखंड में तेजी से पर्यटन का विकास हुआ है। सेवा क्षेत्र के सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) में पर्यटन का अंश 50 प्रतिशत और राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 5 प्रतिशत है। यह राज्य की 2 प्रतिशत आबादी को रोजगार देता है। इस हिमालयी राज्य के उत्तर में चीन (तिब्बत) और पूर्व में नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमाएँ लगती हैं। यहां कई धार्मिक स्थलों और हिल स्टेशनों से लेकर राष्ट्रीय

## आतिथ्य परियोजनाओं के लिए पूंजीगत सब्सिडी

क्षेत्र श्रेणी	अधिकतम पूंजी सब्सिडी
श्रेणी ए क्षेत्रों में परियोजनाएं	पात्र पूंजीगत संपत्ति का 25%
श्रेणी बी क्षेत्रों में परियोजनाएं	पात्र पूंजीगत संपत्ति का 35%
श्रेणी सी क्षेत्रों में परियोजनाएं	पात्र पूंजीगत संपत्ति का 50%

- गंगा के अलावा शेष नदियों में राफिटिंग ऑपरैटर का शुल्क माफ
- टिहरी में पैराग्लाइडिंग ट्रेनिंग फ्री
- इंनवेसमेंट प्रमोशन सेल का निर्माण

उद्यानों और जैव-भंडार तक स्थित हैं जो दुनिया भर से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। उत्तराखंड गंगा व यमुना सहित भारत की कई प्रमुख नदियों का उद्गम स्थल है। नंदा देवी, बद्रीनाथ और कामेट जैसी बर्फ से ढकी पर्वत चोटियों विहंगम दृश्य दिखलाती हैं, जबकि बांज, बुरांश और देवदार के घने जंगल किसी को भी कौतुहल से भर देते हैं। तराई के क्षेत्र में भी कॉरबेट टाइगर रिजर्व तथा राजाजी नेशनल पार्क जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य बाबा, तेंदुआ व हाथी सहित बड़ी संख्या में पशु-पक्षियों का आवास स्थल हैं। उत्तराखंड, अपनी प्राकृतिक और सांस्कृतिक विविधता के साथ, इतिहासकारों, ट्रेकिंग उत्साहियों, योग चिकित्सकों, मानव-विज्ञानियों पशु-पक्षी-विज्ञानियों, प्रकृतिवादियों, भाषाविदों और भूवैज्ञानिकों के लिए स्वर्ग से कम नहीं।

अपने रमणीय आकर्षण और शांति के कारण है कि उत्तराखंड शानदार कल्याण केंद्रों के लिए एक आदर्श स्थान है जो चिकित्सीय गुणों के साथ शरीर की गंदगी

## नमो विजन से संवर रहा है उत्तराखंड



बाहर निकालने (डेटॉक्सीफिकेशन) और आरामदायक आयुर्वेदिक स्पा प्रदान करते हैं। घने जंगलों, घुमावदार पहाड़ियों, हरे-भरे घास के मैदानों, बर्फीली ढलानों और शक्तिशाली पर्वत श्रृंखलाओं की पृष्ठभूमि में बना,

प्रदान करता है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है कि सरकार पर्यटन को आधुनिक सुविधाओं व गतिविधियों से जोड़ कर एक लुभावना अनुभव बनाने को दृढ़ संकल्पित है। उनका कहना है कि सरकार प्रदेश में

नए मंदिर सर्किट, रोपवे और एडवेंचर ट्रेल्स की स्थापना

मिलेगा। धामी ने आगे कहा कि पिछले महीने राज्य की अपनी यात्रा के दौरान, प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा था कि राज्य में पर्यटन और तीर्थयात्रा सर्किट के विकास के लिए डबल इंजन सरकार के प्रयास अब फलित होने लगे हैं। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड एक दिव्य भूमि है जहां हर कोने में देवी-देवताओं का वास है। मंदिरों का महत्व केवल आस्था का केंद्र होने तक सीमित नहीं बल्कि उनका योगदान स्थानीय अर्थव्यवस्था में भी काफी महत्वपूर्ण है।

21वीं सदी के विकसित भारत के निर्माण के दो प्रमुख स्तंभ हैं। पहला, अपनी विरासत पर गर्व और दूसरा, विकास के लिए हर संभव प्रयास आज उत्तराखंड, इन दोनों ही स्तंभों को मजबूत कर रहा है।

नरेन्द्र मोदी, प्रधानमंत्री

## नदियों से आसमान तक

### पर्यटन को लगे पंख



देहरादून के मालदेवता क्षेत्र में पैराग्लाइडिंग करता युवक



स्क्रीडिंग: भारत की स्क्रीडिंग राजधानी के रूप में जाना जाने वाला औली नौसिखिण और विशेषज्ञ स्क्रीडर दोनों के लिए पसंदीदा गंतव्य है। यह हिल स्टेशन अत्याधुनिक स्क्रीडिंग सुविधाओं से उपयुक्त है तथा इसकी ढलानें पीक सीजन (दिसंबर से मार्च) के दौरान गहरी बर्फ से ढकी रहती हैं और शंकुधारी जंगलों से घिरी रहती हैं। लेकिन राज्य में स्क्रीडिंग के लिए औली एकमात्र स्थान नहीं है। कुछ कम प्रसिद्ध लेकिन समान रूप से सुंदर स्थान मुनस्यारी, मुंडाली और दरया बुचाल भी हैं, जिनकी ढलान 28 वर्ग किमी है और वे भी स्क्रीडिंग के लिए उपयुक्त स्थान बन सकते हैं।

## साहसिक पर्यटन

पर्यटन का केंद्र कहे जाने वाले उत्तराखंड में तीर्थारटन के साथ ही साहसिक पर्यटन गतिविधियां भी देश-विदेश के सैलानियों को आकर्षित कर रही हैं। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड की ओर से एयर और वाटर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। इससे व्यापक स्तर पर उत्तराखंड के साहसिक पर्यटन को पहचान मिलती दिख रही है। खासकर पर्वतीय क्षेत्रों में पर्यटन के साथ रोजगार सृजन की दिशा में भी प्रदेश आगे बढ़ रहा है। चारधाम समेत तमाम मठ-मंदिरों की आध्यात्मिक शक्तियों के आगे नतमस्तक विश्व अब उत्तराखंड में पर्यटन गतिविधियों के लिए भी खिंचा आ रहा है।

### देश में पहली बार उत्तराखंड में जाइरोकॉप्टर एडवेंचर की शुरुआत

जाइरोकॉप्टर द्वारा भारत की पहली हिमालयन एयरसफारी के लॉन्च के साथ ही उत्तराखंड ने पर्यटन में एक नयी पहल की है जो हिमालय के लुभावने दृश्यों के साथ रोमांच का मिश्रण करते हुए अद्वितीय अनुभव प्रदान करने का वादा करता है। उत्तराखंड पर्यटन विकास बोर्ड के अपर

मुख्य कार्यकारी अधिकारी के अनुसार

पर्यटन विभाग की ओर से प्रदेश में साहसिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। धार्मिक स्थलों को विकसित करने और सुविधाओं में इजाफा करने की दिशा में पर्यटन विभाग कदम बढ़ा रहा है। बायोग्रवर के बागनाथ धाम को विकसित करने के लिए सर्वे



कर लिया गया है। 49 करोड़ रुपये की लागत से यहां विभिन्न कार्य किए जाएंगे। बागनाथ धाम के साथ ही सरयू घाटों का सौंदर्यीकरण भी प्रस्तावित है। चारधाम यात्रा के लिए हेलीसेवा को बुकिंग आइआरसीटीसी को दिए जाने के बाद इस बार बंपर श्रद्धालु हवाई मार्ग से चारधाम पहुंचेंगे।

### एयर स्पोर्ट्स के क्षेत्र में किए गए प्रयास

- नेनीताल में नौ कंपनियों टैंडेम पैराग्लाइडिंग संचालित कर रही हैं। हाट एयर बैलूनिंग का संचालन भी शुरू हुआ है।
- विश्व पर्यटन दिवस पर मसूरी के जार्ज एवरेस्ट में हिमालय दर्शन के लिए एयर सफारी की शुरुआत की गई। साथ ही पैरामोटर गतिविधियों की प्रदर्शनी व एयरोमाइलिंग गतिविधियां भी आयोजित की गई।
- हरिद्वार के बैरगी कैंप में एयरो एडवेंचर स्पोर्ट्स के तहत हाट एयर बैलूनिंग, जायरोकॉप्टर,

ट्रेकिंग: है जो आपको कई हिमालय शिखरों और चोटियों के रहस्यमय परिवेश में ले जाएगी। राज्य के ट्रेकिंग रूट भरपूर रोमांच और मनोरम दृश्यों से आपको रूबरू कराते हैं। इनमें फू चोपता, और चंद्रशिला ट्रेक और नंदा देवी ट्रेक शामिल हैं।



फ्लिक्स विंग और स्काई गोजिंग गतिविधियों को पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू करने की कवायद।

कुमाऊं मंडल के चोपत जनपद में हैंग ग्लाइडिंग एवं पैरामोटरिंग की गतिविधियां बड़े पैमाने पर शुरू की गई हैं।

### वेडिंग डेस्टिनेशन: संवरेगी आर्थिकी

देवभूमि उत्तराखंड धार्मिक व आध्यात्मिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। यही कारण है कि सरकार इस मध्य हिमालयी राज्य में तीर्थारटन व पर्यटन पर विशेष जोर दे रही है और इसी क्रम में सुविधाएं भी विकसित की जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने अब उत्तराखंड को वेडिंग डेस्टिनेशन के तौर पर विकसित करने का भी मंत्र दिया है। यद्यपि, राज्य में धार्मिक, आध्यात्मिक व प्राकृतिक स्थलों में लोग विवाह समारोह आयोजित करने में रुचि ले हैं, लेकिन अब प्रधानमंत्री की सलाह से इन प्रयासों को न केवल गति मिलेगी, बल्कि स्थानीय आर्थिकी भी संवरेगी। उत्तराखंड में मसूरी, नेनीताल, रामनगर समेत सर्व सुविधासंपन्न स्थलों में देश-विदेश से आकर विवाह का चलन बढ़ा है। विशुद्ध रूप से प्रकृति की गोद में विवाह के लिए औली जैसे स्थल भी यहां हैं। राज्य में प्रमुख विवाह गंतव्य स्थल- त्रिविणीनारायण, शांतिकुंज हरिद्वार, ऋषिकेश, जोशीमठ, मसूरी, देहरादून, औली, चकराता, हर्षित, काणताल, टिहरी झील, नरेन्द्रनगर, नेनीताल, रामनगर, ब्रह्मताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, भीमताल, मुक्तेश्वर, रामगढ़, रानीगढ़, नोकुंजियाल, घोड़ाखाल, गोल्ड्यू मंदिर, चिर्वाई गोल्ड्यू मंदिर आदि।

## मानसखंड मंदिर माला मिशन कुमाऊं के प्राचीन मंदिरों का होगा विकास



केदारनाथ व बद्रीनाथ के तर्ज पर कुमाऊं के पौराणिक और प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए अवस्थापनात्मक विकास किया जाएगा। मानस खंड मंदिर माला मिशन योजना के अंतर्गत जागेश्वरधाम मंदिर विकसित होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धार्मिक स्थलों के विकास के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। जागेश्वर धाम उत्तराखंड का पांचवा धाम है, इसकी महत्ता का स्कंद पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण में भी उल्लेख है। पुराणों के अनुसार भगवान शिव एवं सप्तऋषियों ने यहां तपस्या की थी। साथ ही जागेश्वर धाम समेत अन्य धार्मिक स्थलों के लिए मास्टर प्लान बनाए जाएंगे। धामी ने कहा कि भारत माला योजना से सभी धार्मिक स्थलों का उत्थान होगा। प्रदेश के विकास के लिए अगले दस सालों का रोडमैप तैयार किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में जितना धर्म, संस्कृति और धार्मिक स्थलों का उत्थान हुआ, उतना विश्व में किसी ने भी नहीं सोचा। जागेश्वर में लगभग 250 छोटे-बड़े मंदिर हैं। जागेश्वर मंदिर परिसर में 125 मंदिरों का समूह है। मंदिरों का निर्माण

जागेश्वर, हनोल, गुंजी, आदि कैलाश का केदारनाथ जैसा विकास, मास्टर प्लान हुआ तैयार, 162 करोड़ से ज्यादा का बजट

बड़ी-बड़ी शिलाओं से किया गया है। जागेश्वर धाम में सारे मंदिर केदारनाथ शैली से बने हुए हैं। मान्यता है कि गुरु आदि शंकराचार्य ने केदारनाथ प्रस्थान करने से पहले जागेश्वर के दर्शन किये। कुमाऊं क्षेत्र में भी पौराणिक महत्व के अनेक मंदिर हैं जिन्हें मानसखंड योजना के अंतर्गत जोड़ने की योजना है। सरकार ने कुमाऊं क्षेत्र में 16 मंदिरों में बुनियादी ढांचे को विकसित करने के लिए मानसखंड मंदिर माला परियोजना शुरू की है। अल्मोड़ा के जागेश्वर धाम में जल्द ही योजनाएं शुरू होंगी। पिथौरागढ़ जिले के हनोल और गुंजी में महासु देवता मंदिर का मास्टर प्लान अनुमोदन के अंतिम चरण में है। इस दृष्टिकोण के साथ, इन स्थानों पर समय बुनियादी ढांचे में सुधार होने की उम्मीद है।

## वाइब्रेट विलेज: सीमावर्ती 51 गांवों में लौटेगी रौनक

उस मुल्क की सरहद को कोई छू नहीं सकता, जिस मुल्क की सरहद की निगहबान हैं आंखें।' इन आंखों की चमक और सशक्त हो, यही तो है केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी वाइब्रेट विलेज कार्यक्रम का उद्देश्य। देश के अन्य हिस्सों की भांति स्वाभाविक तौर पर चीन और नेपाल की सीमा से सटे उत्तराखंड के गांवों को भी इस कार्यक्रम का लाभ मिलना तय है। केंद्र ने सीमावर्ती गांवों के व्यापक विकास के लिए इस कार्यक्रम के तहत अब तक देशभर में 19 जिलों के 46 विकासखंडों के 2967 गांवों की पहचान की है। कार्यक्रम के प्रथम चरण में 662 गांव लिए गए हैं। इसमें उत्तराखंड के 51 गांव भी शामिल हैं, जिनके चहुंमुखी विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर ली गई है। 758 करोड़ रुपये की लागत से यहां के तीन जिलों पिथौरागढ़, चमोली व उत्तरकाशी के पांच विकासखंडों के इन गांवों के लिए विभिन्न क्षेत्रों में 510 कार्य प्रस्तावित किए गए हैं। अब केंद्र से बजट अवमुक्त होते ही इन कार्यों में तेजी आएगी और सीमावर्ती गांव जीवंत होंगे।

### एक नजर में सीमा क्षेत्र

- 375 किलोमीटर है चीन से लगी सीमा
- 283 किलोमीटर सीमा है नेपाल से सटी
- 510 कार्य विभिन्न सेक्टर में होंगे वाइब्रेट विलेज
- 758 करोड़ से संवरेगी 51 सीमावर्ती गांव

### भविष्य की उम्मीदें

- सीमावर्ती गांवों के विषम भूगोल को ध्यान में रख बनेगी योजनाएं।
- स्थानीय ग्रामीणों का सुधरेगा जीवन स्तर।
- शीतकाल में बर्फबारी होने पर भी जीवंतता बनी रहेगी।
- नेलांग घाटी में पूर्व में वीरान हुए गांवों में लौटेगी रंगत।



## राज्य में होम-स्टे से गांव-गांव पहुंच रहा पर्यटन

उत्तराखण्ड सरकार की होम-स्टे योजना राज्य में न केवल पलायन को रोकने में बहुत कारगर रही है। साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार व पर्यटन के नये-नये क्षेत्रों का विकास भी हो रहा है। पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए सरकार की इस पहल से पर्यटन आज गांव-गांव पहुंच रहा है। योजना के अन्तर्गत भवन स्वामी, जो परिवार सहित भवन में निवास करता हो, अतिथियों के लिये न्यूनतम एक तथा छः कक्षों की व्यवस्था की गई है। यह योजना

उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिये है। पारम्परिक/ पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। यह योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त करने के लिये नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आर्थिक साज-सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये योजना का लाभ अनुमन्य होगा। होम स्टे के कॉन्सेप्ट को बहुप्रचारित किया जा रहा है, पंजीकृत होम-स्टे को घरेलू दर पर बिजली व पानी की व्यवस्था भी की गई है।

उत्तराखण्ड के मूल/स्थायी निवासियों के लिये है। पारम्परिक/ पहाड़ी शैली में निर्मित/विकसित भवनों को प्राथमिकता दी जायेगी। यह योजना नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर सम्पूर्ण प्रदेश में लागू है। प्रोत्साहन एवं लाभ प्राप्त करने के लिये नये गृह आवास के निर्माण के अतिरिक्त पुराने भवनों की आर्थिक साज-सज्जा, उनका विस्तार/नवीनीकरण/ सुधार एवं शौचालयों के निर्माण के लिये योजना का लाभ अनुमन्य होगा। होम स्टे के कॉन्सेप्ट को बहुप्रचारित किया जा रहा है, पंजीकृत होम-स्टे को घरेलू दर पर बिजली व पानी की व्यवस्था भी की गई है।

## सम्पादकीय

## भारत की रूस चिंता

विदेश मंत्री जयशंकर के हालिया भाषणों से भारत की यह इच्छा जाहिर होती है कि पश्चिमी देश भारतीय जरूरतों के मुताबिक अपनी नीतियों को ढालें। वे ऐसा रख ना अपनाएं, जिससे रूस ज्यादा से ज्यादा चीन के करीब चला जाए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पिछले हफ्ते एक जर्मन अखबार को दिए इंटरव्यू में पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद रूस से तेल खरीदने के भारत के फैसले का बचाव किया। कहा कि मॉस्को ने कभी भी भारत के हितों को नुकसान नहीं पहुंचाया है। दोनों देशों के बीच हमेशा स्थिर और दोस्ताना संबंध रहे हैं। ये बात जयशंकर ने ठीक उस समय कही, जब रूसी विपक्षी नेता एलेक्सी नवालनी की मौत से पश्चिमी देश भड़के हुए थे। साथ ही यूक्रेन युद्ध के दो साल पूरा होने वाले थे। इस मौके पर अमेरिका और यूरोपीय देशों ने रूस पर पांच सौ नए प्रतिबंध लगाने का एलान किया, जिसके दायरे में रूस से कारोबार करने वाली कुछ भारतीय कंपनियां भी आ गई हैं। उसी माहौल के बीच नई दिल्ली में रायसीना डायलॉग को संबोधित करते हुए जयशंकर ने कहा कि पश्चिमी देशों को चाहिए कि वे दरवाजे बंद करने के बजाय रूस को अधिक विकल्प उपलब्ध कराएं, ताकि वह चीन के ज्यादा करीब ना चला जाए। विदेश मंत्री ने यहां चीन के खिलाफ अपनी नाराजगी फिर जताई। कहा कि चीन को 'माइंड गेम' खेलने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, जो अन्य देशों को सहभागियों के साथ मिलकर काम करने से रोकना चाहता है। निहितार्थ यह कि चूंकि भारत ने अमेरिका के साथ सहभागिता बनाई है, इसलिए चीन ने भारत के खिलाफ सख्त रख अपना रखा है। वह चाहता है कि भारत अमेरिका से दूरी बनाए, तब वह 2020 में सीमा पर बने गतिरोध को दूर करने पर राजी होगा। जयशंकर के इन भाषणों से भारत की यह इच्छा जाहिर होती है कि पश्चिमी देश भारतीय जरूरतों के मुताबिक अपनी नीतियों को ढालें। संभवतः भारत सरकार की समझ यह है कि अमेरिका की चीन विरोधी रणनीति में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए वह पश्चिमी नीति को प्रभावित कर सकने की स्थिति में है। मगर असल में ऐसा होता नहीं दिख रहा है। निज्जर और पजू मुद्दों के बाद तो स्थितियां और प्रतिकूल हो गई हैं। ऐसे में रूस भले भारत के लिए महत्वपूर्ण हो, लेकिन उस वजह से पश्चिम की सोच ढलेगी, इसकी न्यूनतम संभावना ही है।

## हैमशायर और नवादा

राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनने की दौड़ को ही लें। ट्रंप ने इसके लिए हुई एक भी डिबेट में भाग नहीं लिया, बल्कि वे ऐसा व्यवहार करते थे मानों वे राष्ट्रपति हों, न कि मौजूदा राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रयासरत एक उम्मीदवार। ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी में इस हद तक बोलबाला है कि पार्टी के अन्य प्रमुख नेता उनके चापलूस नजर आते हैं जो ट्रंप की कृपाहीन चाहते हैं। यहां तक कि फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसांटिस ट्रंप के उपहास और दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद भी व्हाइट हाउस में उनकी वापसी की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं। उनका समर्थन प्रायमरी की दौड़ में किसी भी रिपब्लिकन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें पहले से ही अधिकांश प्रमुख निर्वाचित रिपब्लिकनों का समर्थन हासिल है। वे चुनावी चंदा हासिल करने और मत हासिल करने में भी बहुत आगे हैं। इस तरह ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी नहीं रही। बल्कि वह ट्रंप की सनक और इच्छा के अनुसार चलने वाली पार्टी नजर आती है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी रिपब्लिकनों को उनका सामना करने के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं मिल पाया। वे मतदाताओं के समक्ष कोई नया नेता प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहे। आज के मतदाता दुनिया के किसी भी इलाके के मतदाताओं की तरह ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके जैसी बातें करे, जो कुलीन न लगे और जो उनकी ओर से उनके शत्रुओं का मुकाबला कर सके।



मिक्लौद राष्ट्रपति को पद से हटाने के लिए प्रयासरत एक उम्मीदवार। ट्रंप का रिपब्लिकन पार्टी में इस हद तक बोलबाला है कि पार्टी के अन्य प्रमुख नेता उनके चापलूस नजर आते हैं जो ट्रंप की कृपाहीन चाहते हैं। यहां तक कि फ्लोरिडा के गवर्नर रोन डेसांटिस ट्रंप के उपहास और दुर्व्यवहार का सामना करने के बाद भी व्हाइट हाउस में उनकी वापसी की कोशिशों का समर्थन कर रहे हैं। उनका

समर्थन प्रायमरी की दौड़ में किसी भी रिपब्लिकन की सबसे बड़ी पूंजी है। उन्हें पहले से ही अधिकांश प्रमुख निर्वाचित रिपब्लिकनों का समर्थन हासिल है। वे चुनावी चंदा हासिल करने और मत हासिल करने में भी बहुत आगे हैं। इस तरह ग्रैंड ओल्ड पार्टी अब ग्रैंड ओल्ड पार्टी नहीं रही। बल्कि वह ट्रंप की सनक और इच्छा के अनुसार चलने वाली पार्टी नजर आती है। ट्रंप के राष्ट्रपति चुनाव हारने के बाद भी रिपब्लिकनों को उनका सामना करने के लिए कोई दमदार चेहरा नहीं मिल पाया। वे मतदाताओं के समक्ष कोई नया नेता प्रस्तुत करने में नाकामयाब रहे। आज के मतदाता दुनिया के किसी भी इलाके के मतदाताओं की तरह ऐसा नेता चाहते हैं जो उनके जैसी बातें करे, जो कुलीन न लगे और जो उनकी ओर से उनके शत्रुओं का मुकाबला कर सके। ट्रंप ने वे सारी खूबियां प्रदर्शित की हैं। श्वेत पुरुष और महिलाएं, जो कालेज नहीं गए, रिपब्लिकन पार्टी के मतदाताओं का प्रमुख हिस्सा हैं। वे ट्रंप को लेकर अतिउत्साहित हैं। उन्हें ट्रंप के रूप में ऐसा नेता नजर आता है जो उनके लिए संघर्ष करने को उद्यत है। अन्य कोई भी उम्मीदवार

वह सिद्ध नहीं कर सका कि वह ट्रंप से बेहतर साबित हो सकता है। बल्कि वे अपने राजनीति करने के तौर-तरीकों से मतदाताओं से दूर बने रहे। निजी हैली और माईक पेंस ट्रंप के दौर के पहले के नेताओं के रंग-ढंग में नजर आए। रोन डेसांटिस और मिक्लौद रामास्वामी ने ट्रंप की नकल करने की हर संभव कोशिश की। उन्होंने अपने आप को मेक अमेरिका ग्रेट अगेन एजेंडे के अपेक्षाकृत युवा और बेहतर पैरोकार के रूप में पेश करने की कोशिश की। मगर वे ट्रंप और उनके व्यक्तित्व का विकल्प प्रस्तुत नहीं कर सके बल्कि उन्होंने अपने संसाधन इस प्रयास में खर्च कर दिए कि उन्हें ट्रंप समर्थकों की नाराजगी न झेलनी पड़े। डिबेटों, साक्षात्कारों, रैलियों के दौरान वे ट्रंप की ओर से सफाई देते रहे, उन पर लगे आपराधिक आरोपों के बारे में चुपकी साधे रहे। बल्कि वे ट्रंप को शहीद साबित करनी में जुटे रहे और ट्रंप पर हो रही कानूनी कार्यवाही को बाईं-डन द्वारा उन्हें सताना बताते रहे। वे उनकी छवि हाल के समय के महानतम राष्ट्रपति की बनाते रहे। जब तक कि पीईडब्ल्यू द्वारा किए गए संशोधन के

## बिहार, झारखंड में कांटे की लड़ाई

## हरिशंकर व्यास

भारतीय जनता पार्टी 370 के लक्ष्य को हासिल करने के लिए जिन राज्यों में पिछली बार का प्रदर्शन दोहराने की उम्मीद कर रही है उनमें बिहार और झारखंड दोनों शामिल हैं। बिहार में पिछली बार 40 में से 39 सीटें पकड़ीं एक मिला थी जिसमें भाजपा को अकेले 17 सीटें मिली थी। इस बार भाजपा को इसमें मुश्किल दिख रही थी तो उसने किसी तरह से राजद और जदयू का गठबंधन तैयार कर नीतीश कुमार के साथ तालमेल किया है। इसके बावजूद भाजपा को गारंटी नहीं है कि वह पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी।

इसी तरह झारखंड में भाजपा और उसकी सहयोगी को राज्य की 14 में से 12 सीटें मिली थीं। लेकिन उसके तुरंत बाद हुए विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा ने उसे हरा दिया था। तब से भाजपा किसी तरह से सरकार को अस्थिर करने में लगी थी। चुनावी साल में जेएमएम नेता हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने विपक्ष का वोट एकजुट किया है। यहां आधा दर्जन सीटों पर भाजपा के लिए मुश्किल लड़ाई दिख रही है। ओवरऑल वोट में भाजपा बहुत आगे है। उसे 56 फीसदी वोट मिले थे, जबकि जेएमएम और कांग्रेस अलायंस को 35 फीसदी वोट मिले थे।

यानी 21 फीसदी वोट का अंतर था। लेकिन सीटवार देखें तो पिछले लोकसभा चुनाव में झारखंड में भाजपा ने लोहरदगा, खूंटी और दुमका सीट बहुत कम अंतर से जीती थी। खूंटी में अर्जुन मुंडा महज डेढ़ हजार वोट से जीते थे, जबकि लोहरदगा सीट पर सुदर्शन भगत 10 हजार वोट से जीते थे। दुमका में सुनील सोरेन ने शिवू सोरेन को 47 हजार वोट से हराया था। इन तीन सीटों पर कांग्रेस और जेएमएम गठबंधन कम अंतर से हारा था और दो सीटों— चाईबासा व राजमहल में जीत मिली थी। सो. कम से कम पांच लोकसभा सीटें ऐसी हैं, जहां विपक्ष गठबंधन

मजबूत है। पिछली बार के मुकाबले विपक्ष का गठबंधन इस बार बेहतर स्थिति में इसलिए भी है क्योंकि पांच साल राज्य में भाजपा के तमाम प्रयासों के बावजूद न जेएमएम में कोई टूट हुई और न कांग्रेस टूटी। हेमंत सोरेन के इस्तीफा देने और गिरफ्तारी के बाद भी चम्पई सोरेन के साथ सभी विधायक एकजुट रहे। बिहार में भाजपा को पता था कि राजद, जदयू, कांग्रेस और लेपट का गठबंधन ज्यादा मजबूत है इसलिए नीतीश कुमार को उसने अपने साथ मिलाया। ओवरऑल वोट में भाजपा, जदयू और लोजपा गठबंधन को 23 फीसदी वोट की बड़

धी। इनकी 53 फीसदी तो कांग्रेस और राजद गठबंधन को 30 फीसदी वोट मिले थे। लेकिन सीटवार मुकाबले में कई सीटें बहुत कंटे की टक्कर वाली थीं। मिसाल के तौर पर जहानाबाद सीट पर राजद के सुरेंद्र यादव सिर्फ साढ़े 17 सौ वोट से हारे थे। पाटलिपुत्र सीट पर मीसा भारती 39 हजार वोट हारी थी तो कटिहार सीट पर कांग्रेस के तारिक अनवर 57 हजार वोट से हारे थे। राजद और कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां काराकाट और औरंगाबाद सीट पर भी एक लाख से कम वोट से हारी थी। विपक्षी गठबंधन सिर्फ एक किशनगंज सीट जीत पाया था।

## यामी गौतम की आर्टिकल 370 की कमाई में गिरावट



इन दिनों सिनेमाघरों में यामी गौतम की बहुप्रतीक्षित फिल्म आर्टिकल 370 लगी हुई है, जो दर्शकों का भरपूर मनोरंजन कर रही है। विद्युत जामवाल की फिल्म नैक्स से भिड़त के बावजूद यामी की फिल्म ने दर्शकों का दिल जीत लिया है। आर्टिकल 370 का शुरुआत से दर्शकों का खूब प्यार मिल रहा है। हालांकि, वीके ड पर बंपर कमाई करने के बाद अब कामकाजी दिनों में फिल्म की कमाई में भारी गिरावट देखने को मिली है। अब आर्टिकल 370 की कमाई के चौथे दिन के आंकड़े सामने आ चुके हैं। वॉक्स ऑफिस ट्रैकर सैकनलिक के मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को 3.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल वॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26.15 करोड़ रुपये हो गया है। आर्टिकल 370 ने टिकट खिडकी पर 5.9 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था। वीके ड पर फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसने दूसरे दिन 7.4 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 9.6 करोड़ रुपये कमाए। आर्टिकल 370 के निर्देशन की कमान आदित्य सुहास जंभाले ने संभाली है और फिल्म का निर्माण यामी के पति और निर्देशन आदित्य धर ने किया है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के दौरान

मुताबिक, फिल्म ने सोमवार को 3.25 करोड़ रुपये का कारोबार किया, जिसके बाद इसका कुल वॉक्स ऑफिस कलेक्शन 26.15 करोड़ रुपये हो गया है। आर्टिकल 370 ने टिकट खिडकी पर 5.9 करोड़ रुपये के साथ अपना खाता खोला था। वीके ड पर फिल्म की कमाई में उछाल आया और इसने दूसरे दिन 7.4 करोड़ रुपये और तीसरे दिन 9.6 करोड़ रुपये कमाए। आर्टिकल 370 के निर्देशन की कमान आदित्य सुहास जंभाले ने संभाली है और फिल्म का निर्माण यामी के पति और निर्देशन आदित्य धर ने किया है। यह फिल्म जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाए जाने के दौरान

## वर्ल्डवाइड 150 करोड़ की ओर शाहिद-कृति की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया

शाहिद कपूर और कृति सेनन की फिल्म तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का बिजनेस हिक्कोले रहा है। फिल्म भारत में पिछली जा रही है, लेकिन वर्ल्डवाइड तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का कलेक्शन आगे बढ़ रहा है। अब फिल्म ने 150 करोड़ वकब की ओर निशाना साधा है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के लिए अब बिजनेस करना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि मुकाबले में दो नई फिल्में आ गई हैं। इनमें यामी गौतम की आर्टिकल 370 और विद्युत जामवाल की नैक्स शामिल हैं। हालांकि, तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया पीछे हटने तो तैयार नहीं है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया वेटेडान वीक के मौके पर रिलीज हुई थी। वही, अब फिल्म ने शिप्टर्स में 18 दिनों का सफर पूरा कर लिया है। वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म काफ़ी पहले 100 करोड़ वकब में एंटी कर गई थी। अब तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया 150 करोड़ की ओर बढ़ रही है। अपडेट के अनुसार 26 फरवरी तक फिल्म ने दुनियाभर में 133.43 करोड़ की ग्रांस कमाई कर ली है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया के डोमेस्टिक बिजनेस रिपोर्ट की बात करें, तो फिल्म ने अभी 100 करोड़ वकब में एंटी नहीं कर पाई है। सैकनलिक की रिपोर्ट के अनुसार, कृति सेनन और शाहिद कपूर की फिल्म ने रिलीज के 18 दिनों में बरतू बॉक्स ऑफिस पर 74.35 करोड़ का नेट बिजनेस कर लिया है। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया की लीड स्टार कास्ट में शाहिद कपूर और कृति सेनन का नाम शामिल है। फिल्म में इनके अलावा डिवल कणाडिया, धर्मद और राकेश बेदी भी महत्व किरदारों में शामिल हैं। फिल्म में कृति सेनन ने सुपर स्मार्ट फीमेल रोबोट सिफा का किरदार निभाया है, जबकि शाहिद ने कंप्यूटर इंजीनियर आरन के रूप में हैं। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया का डायरेक्शन अमित जोशी और आराधना शाह ने किया है।



आधारित है और इस तरह की फिल्मों में समय लागता है। फिल्म में निधि अग्रवाल और बाँबी देओल भी हैं, जो पिछले साल दिसंबर में एमिलि को रिलीज के बाद से सुर्खियों में हैं। उन्होंने आगे कहा, मैंने हाल ही में देखा कि एक विशेष वेबसाइट ने दावा किया है कि फिल्म को बंद कर दिया गया है। अगर मैंने जवाब दिया होता, तो यह एक मुद्दा होता। इसलिए, मैंने बस यह बताया कि फिल्म के लिए वीएफएक्स का काम इंगन, बेंगलुरु, हैदराबाद और अन्य स्थानों पर हो रहा है।

## घरेलू क्रिकेट न खेलने वालों पर बीसीसीआई ने चलाया चाबुक

## सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में श्रेयस अय्यर और ईशान किशन शामिल नहीं

मुंबई, बीसीसीआई ने खिलाड़ियों के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का एलान कर दिया है। कॉन्ट्रैक्ट के तहत श्रेयस अय्यर और ईशान किशन को इसमें शामिल नहीं किया गया है। इन दोनों को कई बार बोलने के बावजूद रणजी ट्रॉफी नहीं खेलने की सजा मिली है और उन्हें नया कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला है। वहीं युवा बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल को पहली बार कॉन्ट्रैक्ट मिला है। बीसीसीआई ने अपने बयान में कहा कि अय्यर और ईशान को चार्जिक अनुबंध नहीं दिया गया है। उत्तर प्रदेश के बाएं हाथ के बल्लेबाज रिंकू सिंह को ग्रेड-सी में जगह मिली है। ए.प्लस ग्रेड



में कप्तान रोहित शर्मा के अलावा विराट जडेजा हैं। बीसीसीआई ने इस साल 30 कोहली, जसप्रीत बुमराह और रवींद्र खिल्लाडियों को अनुबंध दिया है। यह एक

अक्टूबर 2023 से 30 सितंबर 2024 तक के लिए है।

बोर्ड ने इस बार एक नई परंपरा जारी की है। उसने तेज गेंदबाज अनुबंध भी अलग से दिया है। इस लिस्ट में आकाश दीप, विजयकुमार वैश्यक, उमरान मलिक, यश दयाल और विद्युत कावेरिया शामिल हैं। ग्रेड ए प्लस में शामिल खिलाड़ियों को 7 करोड़ रुपये सालाना दिए जाते हैं। इस ग्रेड में शामिल खिलाड़ी तीनों फॉर्मेट में नियमित तौर पर खेलते हैं। ग्रेड ए में शामिल खिलाड़ियों को सालाना 5 करोड़, ग्रेड बी के प्लेयर्स को सालाना 3 करोड़ और ग्रेड सी के प्लेयर्स को सालाना 1 करोड़ रुपये दिए जाते हैं। सालाना कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक 2023-24 के लिए बीसीसीआई ने किसी शर्ष में संशोधन नहीं किया है। बीसीसीआई द्वारा जारी सालाना कॉन्ट्रैक्ट सूची में शर्ष का कोई जिक्र नहीं किया गया है।

## धर्मशाला टेस्ट में केएल राहुल की वापसी पर सस्पेंस

नई दिल्ली, भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जा रहे टेस्ट सीरीज के पांचवें और अंतिम मैच में केएल राहुल की वापसी पर संशय बरकरार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, वह इलाज के लिए लंदन गए हैं। सीरीज में इंग्लैंड के खिलाफ भारत ने 3-1 की अजेय बढ़त बना ली है। सीरीज का आखिरी मैच धर्मशाला में 7 मार्च से खेला जाएगा। वहीं, इस मैच से पहले केएल राहुल की वापसी को लेकर एक बार फिर चर्चा तेज हो गई है। विशाखापत्तनम में दूसरे टेस्ट से पहले बीसीसीआई ने एक बयान में कहा था कि राहुल दाहिने हाँडिस्पेस में दर्द की शिकायत के कारण मैच नहीं खेल पाएंगे। लेकिन, ईएसपीएन क्रिकइन्फो की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि राहुल इस समय जाँच के सामने के हिस्से में चोट के लिए एक विशेषज्ञ से परामर्श लेने के लिए लंदन में हैं। इस कारण उन्हें हैदराबाद में श्रृंखला के शुरुआती मैच से बाहर पक़शन से बाहर होना पड़ा। सीरीज के पहले मैच में राहुल ने 86 और 22 रनों की पारियाँ खेली

## पवन कल्याण की हरि हरा वीरा मल्लू की मेकिंग जारी

तेलुगु सुपरस्टार पवन कल्याण की आने वाली फिल्म हरि हरा वीरा मल्लू ट्रेकर पर है। पहले यह खबर सामने आई थी कि फिल्म अब नहीं बन सकेगी, लेकिन बाद में फिल्म निर्माता ने खुद सामने आकर सभी संशय को खत्म करते हुए स्पष्ट कर दिया कि फिल्म का बनना जारी है।

वहीं, पवन भी जल्द ही फिल्म बनने की प्रक्रिया में हिस्सा लेंगे। फिलहाल, वो आंध्र प्रदेश चुनाव प्रचार में व्यस्त हैं। जैसे ही उनकी व्यस्तता पर विराम लगेगा तो फिल्म निर्माण को नई गति मिलेगी।

फिल्म निर्माता एएम रत्न ने एक सार्वजनिक सभा को संबोधित करने के क्रम में फिल्म से संबंधित सभी अफवाहों का खंडन किया। रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने कहा कि, हरि हरा वीरा मल्लू से उन्हें सिर्फ तेलुगु राज्यों में ही नहीं, बल्कि पूरे देश में एक पावरस्टार के रूप में जाना जाएगा। उन्होंने हाल ही में फिल्म के लिए कुछ दृश्यों की शूटिंग की और चुनाव के बाद फिर से शूटिंग शुरू करेंगे। अगर मैं पैसा कमना चाहता तो मैं उनसे कुछ ही दिनों में फिल्म पूरी करने का आह्वान करता। फिल्म 17वीं सदी पर



उत्तराखण्ड शासन

आज़ादी का  
अमृत महोत्सव

# एक ही लक्ष्य-एक ही सपना सर्वश्रेष्ठ बने उत्तराखण्ड अपना



**पुष्कर सिंह धामी**  
मुख्यमंत्री, उत्तराखण्ड

**नरेन्द्र मोदी**  
प्रधानमंत्री

## आगे बढ़ता उत्तराखण्ड

- मुख्यमंत्री सीमान्त क्षेत्र विकास योजना (एमबीएडीपी)- उत्तराखण्ड राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमा से सटे पांच जनपदों क्रमशः चम्पावत, पिथौरागढ़, चमोली, उत्तरकाशी एवं उ०सि०नगर के 09 सीमान्त विकासखण्डों में आवासित परिवारों को सामुदायिक / समग्र विकास आधारित आजीविका सृजन, स्वरोजगार हेतु कौशल विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन तथा मूल्य संवर्धन, विपणन आदि आवश्यक सतत् आजीविका के संसाधन एवं सुविधायें ससमय उपलब्ध कराना है ताकि सीमान्त क्षेत्रों में पलायन को भी रोका जा सके। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 2000.00 लाख की धनराशि सीमान्त जनपदों हेतु स्वीकृत की गई। जिसके सापेक्ष रु० शत प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।
- मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना का मुख्य उद्देश्य पलायन तथा ग्राम्य विकास निवारण आयोग द्वारा चिन्हित गांवों में आवासित परिवारों / बेरोजगार युवाओं / रिर्वर्स माइग्रेण्ड्स आदि को स्वरोजगार को उपलब्ध कराने हेतु वर्तमान में कियान्वित विभिन्न विभागीय योजनाओं तथा गैप फिलिंग के रूप में इस योजना के तहत आवश्यक वित्तीय सहायता के माध्यम पलायन रोकना तथा रिर्वर्स पलायन को बढ़ावा देना है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल ₹ 2500 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई, जिसके सापेक्ष शत प्रतिशत धनराशि जनपदों को अवमुक्त की जा चुकी है।
- वीर चन्द्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना में वित्तीय वर्ष 2022-23 में 285, वित्तीय वर्ष 2023-24 में सितम्बर, 2023 तक 95 योजना प्रारम्भ (वर्ष 2002) से आतिथि तक 7257 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- दीन दयाल उपाध्याय गृह आवास (होम स्टे) विकास योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2022- 23 में 222, वित्तीय वर्ष 2023 - 24 में सितम्बर 2023 तक 61, योजना प्रारम्भ से आतिथि तक 671 लाभार्थियों को लाभान्वित किया गया।
- ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर होम स्टे के अन्तर्गत 06 जनपदों में 16 ट्रेकिंग ट्रैक्शन सेंटर के अन्तर्गत 99 गांव को अब तक अधिसूचित किया गया है तथा 304 व्यक्तियों का चयन योजना का लाभ प्रदान किया जा चुका है।
- पर्यटन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित Best Tourism Village Competition के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के सरमोली गांव को भारत सरकार की गोल्ड कैटेगरी में Best Tourism Village का अवार्ड प्रदान किया गया।



सूचना एवं लोक सम्पर्क विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा जनहित में जारी

